

- वर्ष**– 6
- अंक**– 12
- रायपुर, शुक्रवार**
21 अगस्त 2026
- पृष्ठ**– 8
- मूल्य**– 3 रु.

॥ स॒ंगछ॒ध्वम् सं॒वद॒ध्वम् ॥

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज—6>>
लंका में प्रवेश और लंकिनी पर प्रहार

लद्दाख में होगी जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

नईदिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लद्दाख के दूरदराज इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय तक पहुंच आसान होगी। अमित शाह के मुताबिक, हाईकोर्ट की बेंच स्थापित होने से लोगों को अपनी कानूनी सेवाओं का लाभ लेने में लाने वाला समय कम होगा।

अमित शाह ने अपने पोस्ट में कहा कि

केंद्र सरकार का यह फैसला लद्दाख के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को बेहतर करेगा। उनके अनुसार, लोगों को उन कानूनी सेवाओं को हासिल करने में कम समय लगेगा, जिनके वे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

सरकार के मुताबिक, हाईकोर्ट की बेंच बनने से लद्दाख के दूरदराज इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्यायिक सेवाओं तक पहुंच बनाने में सुविधा होगी। कानूनी सेवाओं के लिए लगने वाला समय कम होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस फैसले का उद्देश्य लद्दाख में न्याय व्यवस्था तक नागरिकों की पहुंच को और बेहतर करना है। अमित शाह ने अपने पोस्ट



में लद्दाख के विकास के साथ संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और वहां संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लद्दाख में आबादी बिखरे हुए इलाकों में रहती है और लेह तथा कारगिल जैसे

जिलों से जम्मू या श्रीनगर तक पहुंचना कई बार समय, लागत और मौसम की दृष्टि से कठिन होता है। स्थायी बेंच बनने से स्थानीय वादकारियों, वकीलों और अन्य पक्षकारों को लंबी यात्रा से राहत मिलेगी। इससे सुनवाई में भागीदारी आसान होगी और न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुलभ बन सकती है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय है। अभी इसकी दो सीटें श्रीनगर और जम्मू में हैं। लद्दाख बेंच के जुड़ने से न्यायिक ढांचे का विस्तार होगा और क्षेत्रीय जरूरतों के अनुरूप अदालत की उपस्थिति मजबूत होगी।

संसदीय आंकड़ों के अनुसार 30 जुलाई

2026 तक उच्च न्यायालय में 44,557 मामले लंबित थे, जिनमें 6,100 से अधिक मामले ऐसे थे जो दस साल से भी अधिक समय से लंबित हैं। यह आंकड़ा बताता है कि न्यायिक प्रणाली पर दबाव काफी अधिक है। ऐसे में नई बेंच से केवल भौगोलिक पहुंच ही नहीं, बल्कि मामलों के प्रबंधन में भी मदद मिलने की उम्मीद है। लद्दाख में अदालतों के बुनियादी ढांचे की स्थिति भी सीमित रही है। 2025 के अंत में लोकसभा में दिए गए एक जवाब के अनुसार लद्दाख की 10 उप-विभागीय इकाइयों में से केवल पांच में ही अदालत से जुड़ा ढांचा मौजूद था। इनमें जांस्कर, संकू, खलत्सी, नुब्रा और द्रास शामिल थे। यह स्थिति बताती है कि न्यायिक सुविधाओं का विस्तार वहां की तत्काल जरूरत है।

56 नए सिविल जजों की पोस्टिंग, 15 न्यायिक अधिकारियों के तबादले

हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश



बिलासपुर। हाईकोर्ट ने पीएससी के जरिए चुने गए 56 नए सिविल जजों की पोस्टिंग और 15 न्यायिक अधिकारियों के तबादले व पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी विभिन्न आदेशों और अधिसूचनाओं के तहत हायर ज्यूडिशियल सर्विस और लोअर ज्यूडिशियल सर्विस के कई जजों के तबादले किए गए हैं।

इसके साथ ही राज्य शासन द्वारा प्रोबेशन पर नियुक्त 56 नए सिविल जजों (जूनियर डिवीजन) को पहली पदस्थापना दी गई है। इन सभी नव-नियुक्त अधिकारियों को 29 अगस्त तक अपनी पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

हायर ज्यूडिशियल सर्विस के पांच जजों का तबादला: इसके अलावा हायर ज्यूडिशियल सर्विस के पांच जजों का तबादला किया गया है। दंतवाड़ा परिवार न्यायालय के जज हरीश कुमार अवस्थी को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर बनाया गया है। ममता पटेल को अंबिकापुर से द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर और ज्योति अग्रवाल को पेंड्रोरड से न्यायाधीश, राजनांदगांव पदस्थ किया गया है।

दंतवाड़ा से राजनांदगांव तक बदली जिम्मेदारी: नमिता मिंज भास्कर को धमतरी से और एन. सिंह साहू को राजनांदगांव से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), दंतवाड़ा पदस्थ किया गया है। इसके अलावा रायपुर के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज शर्मा को एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) एक्ट के तहत रायपुर विशेष अदालत का विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अंबिकापुर में कमलेश जगदल्ला को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और स्मिता रत्नावत को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाँक्सो) की जिम्मेदारी दी गई है।

सिविल जज सीनियर डिवीजन में सतीश कुमार खाखा को प्रतापपुर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) एवं प्रथम सिविल जज सीनियर डिवीजन, मुंगेली नियुक्त किया गया है। वहीं, भगवान दास पनिका को प्रतापपुर, श्वेता पटेल को छुईखदान, ईशान व्यास को दुर्ग और नीलेश जगदल्ला को राजनांदगांव पदस्थ किया गया है।

जंतर-मंतर प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 5 सदस्यीय समिति

नईदिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा कर्मियों की ओर से कथित तौर पर किए गए अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच के लिए पांच सदस्यीय हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे।



इस पांच सदस्यीय समिति में जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी के अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा और दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस शालिंदर कौर शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक

डॉ. एलआर बिश्नोई भी समिति के सदस्य हैं। समिति प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के कथित अत्यधिक इस्तेमाल से जुड़े आरोपों की जांच करेगी। इसके साथ ही महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित हिंसा और पुलिस निगरानी से जुड़े आरोप भी समिति के दायरे में होंगे। समिति यह भी देखेगी कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से उठाए गए कदम स्थिति के अनुपात में थे या नहीं। इसके अलावा चायलों को दी गई चिकित्सीय सहायता और पीड़ितों को मुआवजे से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जाएगी।समिति केवल प्रदर्शनकारियों की शिकायतों तक सीमित नहीं रहेगी। अधिकारियों की ओर से पुलिस कर्मियों के खिलाफ हुई हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान से जुड़े आरोपों पर भी विचार किया जाएगा। इस तरह समिति प्रदर्शन के दौरान

प्रदेश में जल्द लागू होगा वमिस: डिप्टी सीएम साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग के कामकाज को और अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए जल्द ही ‘वमिस’ (वर्क एंड एकाउंट मॉनिटरिंग इंटीग्रेशन सिस्टम) लागू किया जाएगा। लोक निर्माण से छत्तीसगढ़ निर्माण के मूलमंत्र के साथ विकास को नई गति देने के लिये कार्य किया जा रहा है। राज्य का सबसे बड़ा निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी छत्तीसगढ़ के विकास का आधार है। सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण के साथ विभागीय कार्यों में तेजी और प्रशासनिक कसावट लाने के लिए लगातार कार्य किये जा रहे हैं। ये बातें छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने बुधवार को नवा रायपुर के छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में कहीं।

उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद से अब तक लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर प्रशासकीय स्वीकृतियां मिली हैं। पिछले ढाई साल में विभाग को 12 हजार 666 करोड़ रुपए से अधिक के कुल 1572 कार्यों के

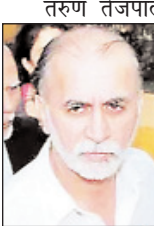


लिए स्वीकृतियां मिली हैं। इसमें सड़क निर्माण के 1285, पुलों के 247 और भवन निर्माण के 42 कार्य शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसम्बर-2023 से मार्च-2024 तक 80 कार्यों के लिए 551 करोड़ 42 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इनमें 374 किमी लंबाई की 72 सड़कें, 6 पुल और दो भवन शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2590 करोड़ 70 लाख रुपए लागत के कुल 438 कार्यों के लिए की स्वीकृति दी गई। इनमें 1465 किमी लंबाई की 400 सड़कें, 37 पुल और एक भवन शामिल हैं।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 लोक निर्माण विभाग के लिए ऐतिहासिक रहा। विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए इस वर्ष 9129 करोड़ 18 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली, जो राज्य निर्माण के बाद पिछले 25 वर्षों के इतिहास में विभाग को मिली सर्वाधिक स्वीकृति है। इस वित्तीय वर्ष में 5129.60 किमी लंबाई की 754 सड़कों, 200 पुलों और 39 भवनों सहित कुल 993 कार्यों को मंजूरी दी गई।

रेप केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पत्रकार तरुण तेजपाल

नईदिल्ली। पत्रकार तरुण तेजपाल ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अब इस फैसले को तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।



सरकार ने मांग की है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए 10 साल की सजा कम है, इसलिए तरुण तेजपाल को उम्रकैद की सजा दी जानी चाहिए।यह मामला नवंबर 2013 का है। गोवा में %तहलका% मैगजीन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक जूनियर पत्रकार ने तरुण तेजपाल पर एक फाइव स्टार होटल के लिफ्ट में यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। इस मामले में तरुण तेजपाल को 30 नवंबर 2013 को गिरफ्तार किया गया था।

राजीव गांधी को प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने जहां सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं,

कांग्रेस महासचिव और उनकी बेटी प्रियंका गांधी अपने पिता की जयंती के मौके पर अपने पति के साथ श्रद्धांजलि देने के लिए वीर भूमि पहुंची और उन्हें याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए राजीव गांधी को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत की विकास यात्रा में उनका भी अहम योगदान रहा है।



सपा नेता आजम खा की और बढ़ सकती हैं मुश्किलें

रामपुर। रामपुर की जेल में बंद सपा नेता आजम खां की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के बीच उनके खिलाफ चल रहे पुराने मामलों की भी चर्चा तेज हो गई है। जौहर विश्वविद्यालय से



जुड़े वित्तीय मामलों की जांच के साथ ही जल निगम भर्ती घोटाला और नियम विरुद्ध सीवरेंज सिस्टम तैयार कर सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला भी लंबित है। ऐसे में आने वाले दिनों में आजम खां की कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामलों में बुधवार को ईडी ने विश्वविद्यालय परिसर समेत आजम खां के करीबियों और उनसे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी की टीम ने वित्तीय लेनदेन, ट्रस्ट की आय-व्यय और विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल धन के स्रोत से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले। जांच का दायरा बढ़ने से अब विश्वविद्यालय के निर्माण में खर्च हुई बड़ी रकम के स्रोत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा जल निगम में भर्ती घोटाले का मामला भी आजम खां के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है।

प्रमुख समाचार

वंदे मातरम विवाद : अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला

नईदिल्ली। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर छिड़ा सियासी घमासान अब और तीव्र हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकारी आयोजनों और पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम का पूरा संस्करण न गाने के कांग्रेस के फैसले पर करारा हमला बोला है। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाते हुए



कहा कि पार्टी वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के खातिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों और राष्ट्रभक्तों के बलिदान का अपमान कर रही है। शाह ने कहा कि 1937 में कांग्रेस ने मुसलमानों को खुश करने के लिए वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांट दिया था। शाह ने कहा, मैं पूरे देश को याद दिलाना चाहता हूं कि 1937 में मुसलमानों को खुश करने के लिए वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। इससे देश के बंटवारे की नींव पड़ी और दो-राष्ट्र सिद्धांत को मजबूती मिली, जिसके कारण आखिरकार देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना। नरेंद्र मोदी सरकार ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर पूरा गीत गाकर और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करके उस ऐतिहासिक गलती को सुधारने की कोशिश की है।

वंदे मातरम के दो पद ही गाएगी कांग्रेस : अख्यर

नई दिल्ली। कांग्रेस ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि पार्टी वंदे मातरम के केवल पहले दो पद गाने की अपनी परंपरा पर कायम रहेगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा तय किए गए रास्ते पर चलेगी, न कि केंद्र सरकार के नए प्रोटोकॉल के मुताबिक। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने आरोप लगाया कि मुसलमानों के प्रति नफरत की वजह से वंदे मातरम के पूरे पाठ को अनिवार्य किया गया है।



कार्यसमिति के उस प्रस्ताव के एक दिन बाद सामने आया, जिसमें 1937 में लिए गए फैसले को दोहराया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि बुधवार को कांग्रेस ने मजबूती से फैसला किया कि हम वंदे मातरम के सिर्फ पहले दो पद गाएंगे। मेरा मानना ​​है कि 1937 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह पर यह तय किया गया था कि हम सिर्फ पहले दो पद गाएंगे और आज हम फिर उसी रास्ते पर चल रहे हैं।

नई मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस पार्टी : नितिन नवीन

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गुरुवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंद मातरम के केवल दो छंद गाने के फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी नई



मुस्लिम लीग बन गई है। नवीन एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शकल दे दी है। उसकी कार्य समिति ने तय किया है कि कांग्रेस के मंचों पर वंदे मातरम के केवल पहले दो छंद ही गाए जाएंगे। भाजपा अध्यक्ष ने 15 अगस्त को कांग्रेस कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाए जाने को लेकर हुए विवाद का भी इशारा में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के आचरण में भी राष्ट्रगीत का यही अपमान दिखाई दिया था। तब कांग्रेस ने उसे संयोग बताकर टाल दिया था। उन्होंने कहा, आज वही अपमान कांग्रेस की नीति बन चुका है।



गाए थे।

उसी वक्त के वीडियो में यह दिखा था कि पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीच में रोकने की कोशिश की थी और भाजपा ने इसे तूल दिया। तब तक कांग्रेस यह कहती रही कि कोई अवरोध पैदा करने की कोशिश नहीं हुई थी। पार्टी ने सभी छंद गाए। लेकिन शायद पार्टी के अंदर यह बड़ा विषय बना और सोनिया गांधी

की जिद के सामने विवश होना पड़ा। कांग्रेस में गांधी परिवार का दबदबा सार्वजनिक है।

1937 के प्रस्ताव को संवैधानिक कानून से बताया ऊपर

अल्पसंख्यक वर्ग का एक तबका पहले से वंदे मातरम का खुला विरोध करता रहा है। वैसे भी नए कानून में किसी के वंदे मातरम न गाने

समाज के लिए। युवाओं के लिए भी यह सही संदेश नहीं होगा क्योंकि कही न कहीं उन्हें भी उकसावा मिल सकता है कि खुलेआम कानून के उल्लंघन की बात करें। पहले वंदे मातरम ,

फिर जन गण मण और तिरंगा।

कांग्रेस का वंदे मातरम के छंद गाने से इनकार

अपमान एक का किया जा सकता है तो दूसरे का क्यों नहीं। अगर एक साधारण व्यक्ति पर कार्रवाई हुई और बड़े चेहरों पर नहीं तो यह लोकतंत्र की सार्थकता पर सवाल होगा। हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि अराजकता की स्थिति पैदा न होने दें।

वस्तुतः कांग्रेस का यह फैसला सीधे तौर पर तो भाजपा के राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देगा। लेकिन धीरे धीरे परिवारवाद और तुष्टीकरण के भाजपा के आरोपों को भी हवा देगा। इसमें किसी को शक नहीं कि 15 अगस्त को कांग्रेस के कार्यक्रम में सभी छह छंद गाए

आशुतोष झा

वंदे मातरम पर कांग्रेस के दो दिन में बदले तेवर ने एक बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक सवाल खड़ा कर दिया है। यह सवाल है कि क्या राजनीतिक विरोध का अधिकार संवैधानिक मूल्यों व अधिकारों से भी बड़ा है। संविधान संसद को अधिकार देता है कि वह जरूरी बहुमत से कानून बनाए और फिर वह हर किसी के लिए बाध्यकारी होता है। उसमें किसी और विकल्प का रास्ता नहीं।

कांग्रेस ने जाहिर तौर पर दबाव में यह कहकर वंदे मातरम के सभी छह छंद गाने से इनकार कर दिया है कि 1937 में कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया था वह संसद के कानून से उपर होगा। वस्तुतः जिस तरह दो दिनों के सोच विचार के बाद कांग्रेस ने यह रुख अपनाया है वह राजनीतिक विरोध अंग्रेजों के जमाने के अवज्ञा आंदोलन की तरह दिख रहा है।

यह न तो राजनीति के सही है और न ही

बनाए तीन तलाक को रद करने के फैसले को भी अमान्य कर सकती हैं। क्या 370 को रद करने के भी विरुद्ध है।

कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। उससे बहुत संवेदनशीलता की अपेक्षा की जाती है। बेशक कांग्रेस को मंदिर चंदा, नौकरी, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर मुखरता से आवाज उठानी चाहिए। लेकिन वंदे मातरम का जिस तरह विरोध किया गया वह राजनीतिक कटुता के चरम पर पहुंचने के साथ ही जल्दबाजी में लिया गया गलत फैसला साबित होगा।

यह किसी क्षेत्रीय दल का आचरण हो सकता था लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का कतई नहीं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मामले में सपा, राजद, तृणमूल जैसे क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस के साथ नहीं हैं। ऐसे नहीं कि इन दलों में कुछ नेताओं के अंदर छटपटाहट नहीं हो लेकिन चुप्पी है।

धमतरी में ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस का धरना

कांग्रेस कार्यकर्ता रामगोपाल अग्रवाल के घर के बाहर पहुंचे और धरने पर बैठे, केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी

धमतरी। शहर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के निवास पर श्वष्ट ने दबिश दी. इस कार्रवाई के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कार्रवाई की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उनके घर के बाहर पहुंच गए और धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और श्वष्ट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रामगोपाल अग्रवाल के धमतरी स्थित आधोगिक वाई स्थित निवास के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता घर के अंदर

कहा: परिवार वालों को परेशान करना गलत



जाकर परिवारजनों से चर्चा करने का प्रयास भी करते नजर आए, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के चलते उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर, पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान एवं पूर्व विधायक, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, पार्षदों समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर ने इसे राजनीतिक ढ़ेष से प्रेरित कार्रवाई बताते हुए कहा कि भाजपा

सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। प्रदेश में कई बड़े मामलों और कथित घोटालों की जांच की मांग उठती रही है, लेकिन उन मामलों पर कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने अयोध्या से जुड़े कथित घोटाले और कुरुद क्षेत्र में भारतमाला परियोजना से जुड़े मामले का जिक्र किया। सवाल उठाया कि आखिर एक परिवार को ही बार-बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस कार्रवाई का विरोध आगे भी करेगी।

धमतरी विधायक ओंकार साहू ने भी श्वष्ट की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि रामगोपाल अग्रवाल का मुख्य निवास रायपुर में है, जबकि धमतरी में उनके परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं। ऐसे में परिवार के लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

धमतरी प्रभारी एवं कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कहा कि रामगोपाल अग्रवाल का मुख्य निवास रायपुर में है और वे लगातार श्वष्ट की हिरासत में हैं। ऐसे समय में धमतरी स्थित उनके परिवार के घर पर कार्रवाई को उन्होंने परिवारजनों को प्रताड़ित करने वाला कदम बताया।

आपको बता दें कि दो अलग-अलग गतिइयों में सुरक्षा बल समेत 8 सदस्य टीम रामगोपाल अग्रवाल के घर दस्तावेजों की जांच कर रही है।

छत्तीसगढ़ के योगेश साहू ने केबीसी में जीते 50 लाख

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के रहने वाले 23 साल के योगेश साहू ने कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) में 50 लाख रुपए जीते हैं। उन्होंने 1 करोड़ रुपए के सवाल का जवाब देने के बजाय गेम क्रिट कर दिया। मुंबई से लौटने के बाद भाटापारा रेलवे स्टेशन पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने योगेश का जोरदार स्वागत किया। उनकी सफलता पर परिवार, गांव और क्षेत्र के लोगों ने खुशी जताई। बता दें कि योगेश के पिता गयाराम साहू महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस के ड्राइवर हैं।

ग्राम टेहका के रहने वाले योगेश आईआईटी बॉम्बे में टॉपर रह चुके हैं। उन्होंने आईआईटीमें पहले ही प्रयास में एडमिशन लिया था। उन्होंने कैंपस प्लेसमेंट में मिली 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वह आईएसएस अधिकारी बनने का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। योगेश ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पिता ने बताया कि योगेश ने व्हस्त सवित्र सेवा की प्रारंभिक परीक्षा भी पहले ही प्रयास में पास की है। वह फिलहाल मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। योगेश मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते और सोशल मीडिया से भी दूर रहते हैं। योगेश



ने शुरुआती पढ़ाई बलौदाबाजार के जेसीज कॉन्वेंट और मयूर शिशु मंदिर से की। इसके बाद वे हाई एजुकेशन के लिए बिलासपुर गए। यहां रोहन चावला ने अपने कोचिंग सेंटर में उन्हें 11वीं और 12वीं की मुफ्त पढ़ाई कराई। तत्कालीन कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने भी उनकी पढ़ाई में मदद की। आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन के लिए मुख्यमंत्री और कलेक्टर की ओर से उन्हें आर्थिक सहायता भी मिली थी। इसके बाद उन्होंने कैंपस प्लेसमेंट में मिली 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ दी। अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के लेटेस्ट एपिसोड में योगेश साहू हॉट सीट पर पहुंचे। 50 लाख रुपए के सवाल में उनसे तस्वीर में दिए गए सवालिया निशान की जगह सही शहर का नाम बताने को कहा गया। टेबल में शहरों के नाम और उनके सामने साल दिए गए थे। इसमें लिखा था- कोलकाता-

1913, ?-1930, स्कोप्जे-1979, शांतिनिकेतन-1998 और विदिशा-2014। इसके चार विकल्प थे-त्रिशूर, मैसूर, अल्मोड़ा और तिरुचिरापल्ली। इस सवाल पर योगेश ने अपनी आखिरी लाइफलाइन 'संकेत सूचक' का इस्तेमाल किया। उन्हें हिंट 'मिला कि सही जवाब तमिलनाडु में स्थित एक शहर है। हिंट मिलने के बाद योगेश समझ गए कि दिए गए साल नोबेल पुरस्कार जीतने के साल हैं और शहर संबंधित नोबेल विजेताओं के जन्मस्थान हैं। इसके बाद योगेश ने सही जवाब तिरुचिरापल्ली चुना। यह सीवी रमन का जन्मस्थान है। उनके जवाब को सही बताया गया और उन्होंने 50 लाख रुपए जीत लिए। इसके बाद योगेश के सामने 1 करोड़ रुपए का सवाल आया। हालांकि, इस पड़ाव पर उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया और 50 लाख रुपये लेकर गेम क्रिट कर दिया।

कोरबा में फैल रहा मलेरिया



नगर निगम की तैयारी अब भी अधूरी, फॉगिंग मशीनें सालों से खराब

कोरबा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बीमारियों और खासकर मलेरिया का खतरा सामने आ चुका है। क्नांचल क्षेत्र नकिया में एक साथ 40 से अधिक मरीज मिले थे। वहीं दूसरी तरफ शहरी इलाकों में इसके रोकथाम के उपाय उप नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि नगर निगम के पास वर्तमान में एक भी चालू फॉगिंग मशीन (धुएं का छिड़काव) नहीं है। अब से लगभग 2 साल पहले निगम शहर के समीप एसईसीएल मुड़ापर के इलाकों में डेंगू फैला था। तब से लेकर अब तक जिले में फॉगिंग मशीन की खरीदी पूरी नहीं की जा सकी है। हाल ही में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर नकिया और आसपास के इलाकों में मलेरिया के मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। जानकारों के

मुताबिक, बरसात के इस मौसम में जलजमाव और नमी के कारण मच्छरों का प्रजनन तेजी से होता है, जिससे मलेरिया और डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे इन मामलों ने स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। शहरी क्षेत्र घनी आबादी और संकरे मोहल्लों से घिरे हुए हैं। पूर्व में इन क्षेत्रों में फॉगिंग मशीनों के जरिए कीटनाशक धुएं का छिड़काव किया जाता था, जिससे न सिर्फ मच्छरों बल्कि अन्य कीट-पतंगों और मौसमी बीमारियों फैलाने वाले जीवाणुओं से भी सुरक्षा मिलती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से नगर निगम की लापरवाही के चलते यह व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है।

कांकेर में रिटर्निंग वॉल टूटने से नदी ने बदला रास्ता

एनीकट सुखा शहर में पानी की किल्लत

कांकेर। छत्तीसगढ़ में जहां मानसून ने चारों ओर पानी ही पानी किया है,वहीं दूसरी ओर कांकेर में शहरवासी पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वजह ये है कि जिस नदी से पानी की सप्लाई की जाती है वो पूरी तरह से सूख चुकी है। इसी वजह से शहर में पानी की सप्लाई नहीं हो रही।आखिर क्यों बारिश में नदी सूखी और पीने के पानी की समस्या हुई आईए जानते हैं। बारिश के मौसम में भी अगर पानी की समस्या खड़ी हो तो ये खबर हैरान करने वाली है।यही



नहीं इससे भी ज्यादा अचंभा ये है कि बारिश में स्टांप डैम खाली है,लिहाजा इंटकवेल के जरिए ना तो पानी मिल सकता है और ना ही पानी को फिल्टर करके उसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। आपको बता दें कि शहर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए दसपुर बागोड़ के बीच बहने वाली महानदी में एनीकट का

निर्माण किया गया था। इस एनीकट के जरिए किसानों को सिंचाई के पानी समेत लोगों को पीने का पानी फिल्टर करके मिलता था। इसके लिए संपवेल का निर्माण किया गया।इसी पानी को फिल्टर करके 21 वार्डों तक पानी पहुंचाया जाता था। बारिश के कारण रिटर्निंग वॉल टूटी पिछले कुछ दिनों से हो रही

लगातार बारिश के कारण नदी में पानी का बहाव तेज हुआ।पानी का बहाव रिटर्निंग वॉल नहीं झेल पाया और वो टूट गया। रिटर्निंग वॉल टूटने के लिए पानी एनीकट की ओर जाने के बजाए दूसरी दिशा में बहने लगा। ये पानी किसानों के खेतों में घुसा जिससे उनकी फसल चोपट हो गई। वहीं दूसरी ओर एनीकट पूरी तरह से खाली हो गया। ऐसे में जब बारिश रुकी तो नदी का आधा से अधिक हिस्सा सूख हुआ है। एनीकट में पानी नहीं होने के कारण लोगों को अब पानी मिलना बंद हो गया है।पिछले दो दिनों से रहवासी पानी के लिए परेशान हैं।

माओवाद मुक्त होने के बाद जिले के अंतिम छोर तक पहुंच रही विकास की रोशनी



तथा एक ही स्थान पर अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना रहा। शिविर में आधार सेवा के अंतर्गत 18 लोगों के नवीन आधार कार्ड बनाए गए तथा 24 लोगों का बायोमैट्रिक अपडेट किया

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

बिछड़े दृष्टिबाधित यात्री को सुरक्षित परिजनों से मिलाया

बिलासपुर। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर वाणिज्य विभाग की स्पेशल सेल ने तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए परिवार से बिछड़े एक दृष्टिबाधित (नेत्र दिव्यांग) यात्री को सुरक्षित खोजकर उनके परिजनों से मिलाया। जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर एक परिवार बिलासपुर से नागपुर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा था। स्टेशन परिसर में यात्रियों की आवाजाही के दौरान परिवार का एक दृष्टिबाधित सदस्य अचानक अपने परिजनों से अलग हो गया। यात्री के लापता होने से चिंतित परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना ऑन-ड्यूटी स्पेशल सेल को दी। सूचना मिलते ही स्पेशल सेल की टीम ने बिना समय गंवाए स्टेशन परिसर में खोजबीन शुरू की। टीम ने स्टेशन के विभिन्न हिस्सों में सघन तलाश करते हुए कुछ ही समय में यात्री को सुरक्षित खोज निकाला और उन्हें उनके परिजनों के संपुर्द किया।अपने परिजन को सकुशल पाकर परिवार ने राहत की सांस ली। परिजनों ने स्पेशल सेल की त्वरित कार्रवाई, संवेदनशीलता और सहयोग के लिए रेलवे प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

एमसीबी जिले के जनकपुर में

भालू की मृतमंेंट

एमसीबी। भरतपुर ब्लॉक मुख्यालय के जनकपुर बस्ती क्षेत्र में भालू की मौजूदगी ने चिंता बढ़ा दी है। बनास नदी के तट पर स्थित कैलाश मंदिर के आसपास इन दिनों जंगली भालू की मृवमंेंट है। सावन माह में कैलाश मंदिर में जलाभिषेक और दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहीं मंदिर के पास एकलव्य आवासीय विद्यालय और कृषि विभाग का कार्यालय भी संचालित है, ऐसे में भालू की नियमित आवाजाही से लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। भालू रोजाना शाम करीब 6-30 से 7 बजे के बीच मंदिर और आसपास के क्षेत्र में पहुंचता है। कई बार वह सुबह के समय भी दिखाई देता है। भालू को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है और कुछ लोग उत्सुकता में उसके बेहद करीब जाकर मोबाइल से फोटो और वीडियो बना रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग भालू को खाने-पीने की सामग्री भी दे रहे हैं। जनकपुर में जंगली भालू की लगातार आमद, श्रद्धालुओं और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता भालू प्रतिदिन यहां आता है।

शराब के नशे में सांप को गले

में डालकर घूमता रहा ग्रामीण

गौरैला पेंड्रा परवाही। जिले के गौरैला थाना क्षेत्र के भदौरा गांव से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां एक ग्रामीण शराब के नशे में पड़ोसी के घर में घुसे फन वाले जहरीले सांप को पकड़कर अपने गले में फंसा लिया और काफी देर तक गांव में घूमता रहा। इस दौरान गांव के लोग उसे ऐसा करने से रोकते रहे लेकिन संतराम शराब के नशे में इतना मस्त था कि किसी की भी बात उसने नहीं सुनी। सांप को गले में डालकर घूमने का वीडियो भी लोगों ने बना लिया जो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान जहरीले सांप ने संतराम को कई बार डसा। सांप के जहर का असर होने पर ग्रामीण सतर्क की हालत भी बिगड़ने लगी। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां से भी मौका पाकर संतराम भाग निकला। अस्पताल के अर्रवाई के बाद से संतराम बैना का कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं ग्रामीणों ने इस तरह जहरीले सांप को पकड़ने और उसके साथ खिलवाड़ करने को बेहद खतरनाक बताया है।

जेवरात किए पार, पुलिस कर

रही सीसीटीवी की जांच

तखतपुर। बिलासपुर जिले के तखतपुर में चोरों ने मंदिर को भी निशाना बना लिया। तखतपुर नगर के कालीबाड़ी स्थित काली मंदिर में बीती रात करीब 2 बजे शांतिर चोरों ने धावा बोलकर दानपेटी में रखी नगदी के साथ सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें दो संदिग्ध नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, चोर मंदिर के पीछे के रास्ते से अंदर दाखिल हुए। इसके बाद उन्होंने मंदिर में रखी दानपेटी को निशाना बनाया और उसमें रखी नगदी निकाल ली। चोर मंदिर में रखे सोने-चांदी के आभूषण भी अपने साथ ले गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चोरी हुए नगदी और जेवरात की कुल कीमत एक लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। वारदात को अंजाम देने से पहले चोरों ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ करने का भी प्रयास किया। हालांकि, इसके बावजूद दो संदिग्ध कैमरे में कैद हो गए। फुटेज के आधार पर पुलिस अब आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है।

उत्कृष्ट कार्य व नवाचार के लिए

छात्रावास अधीक्षक दंपति सम्मानित

महासमुंद। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह-2026 में छात्रावास अधीक्षक दंपति श्री नीलेश खांडे एवं श्रीमती चित्ररेखा तारक को आदिवासी विकास विभाग में उत्कृष्ट कार्य एवं नवाचार के लिए उत्कृष्ट अधिकारी-कर्मचारी सम्मान से नवाजा गया। इस अवसर पर कलेक्टर विनय लंगेह एवं पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार मौजूद रहे। छात्रावास अधीक्षक नीलेश खांडे को यह जिला स्तरीय सम्मान चौथी बार मिला है, जबकि वे राज्य स्तर पर भी दो बार उत्कृष्ट अधीक्षक के रूप में सम्मानित हो चुके हैं। सत्र 2016 में सरायपाली विकासखंड के ग्राम बलौदा छात्रावास में पदस्थतापन के दौरान नीलेश खांडे ने बिना शासकीय मदद के, जन सहयोग से स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी की स्थापना की। जिससे अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र प्रथम श्रेणी में पास होकर प्रयास जैसी संस्थाओं में चयनित होने लगे। इसी प्रकार चित्ररेखा तारक ने प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, बिडिया (बसना) में शैक्षणिक व व्यवस्थागत सुधार कर छात्रावास की कायाकल्प बदल दी।

झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से मासूम की मौत, 3 माह में चौथी घटना

बलरामपुर। झोलाछाप डॉक्टर के इलाज के बाद 3 साल के मासूम अर्भास चेरवा की मौत होने से परिवार में मातम पसरा हुआ है। कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच जारी है। पूरा मामला ग्राम जमुआटांड का है। बताया जा रहा कि 3 महीने के भीतर झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से यह चौथी मौत है।

जमुआटांड निवासी मृतक के पिता रमेश चेरवा के मुताबिक, बच्चे को बुखार था। सरनाडीह में भूलेश्वर सिंह उनका इलाज कर रहा था। मौसमी बुखार के इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाने के बाद मासूम की हालत बिगड़ गई और घर पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई।

जानकारी अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 महीने के भीतर झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से यह चौथी मौत है। घटना के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए

लोगों ने कहा : आखिर झोलाछाप डॉक्टरों पर कब लगेगी लगाम?



स्थानीय लोगों ने कहा कि आखिर झोलाछाप डॉक्टरों पर कब लगाम लगेगी ? फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

इस मामले में कोतवाली प्रभारी भापेंद्र साहू ने कहा कि बुखार आने पर तीन साल के मासूम को परिजन सरनाडीह में झोलाछाप डॉक्टर भूलेश्वर सिंह के पास

लेकर गए थे, जहां इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। शव का पीएम कराया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि हाल ही में बिलासपुर दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने झोलाछाप डॉक्टरों को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में कोई भी झोलाछाप डॉक्टर नहीं है। यहां सभी प्रदेश के हित में अपने-अपने स्तर पर काम कर रहे हैं।

किसी को, किसी के काम को अपमानित करने वाला बात नहीं होनी चाहिए। बिना लाइसेंस, नियम कानून के विपरीत काम करने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अब बलरामपुर क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से मासूम की मौत होने पर स्थानीय लोग स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा रहे।

नम्रता सिंह का गोंड एसटी प्रमाण पत्र सही

शिकायत की जांच के बाद छानबीन समिति ने सुनाया फैसला

मोहला-मानपुर। जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह जैन के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र को लेकर चल रहे विवाद में अब बड़ा अपडेट सामने आया है। शिकायतों के बाद लंबे समय तक चली जांच और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने नम्रता सिंह के गोंड अनुसूचित जनजाति के दावे को सही माना है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह जैन के जाति प्रमाण पत्र को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा था। शिकायतकर्ताओं ने उनके अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाते हुए दस्तावेज, पारिवारिक पृष्ठभूमि और स्थानीय रिकॉर्ड की जांच की मांग की थी। मामला उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति तक पहुंचा। जांच के दौरान संबंधित दस्तावेजों, सरकारी रिकॉर्ड और सामने रखे गए साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। मामले में सुनवाई के



सही माना गया है। जांच में सामने आए रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर समिति ने उनके जाति दावे को स्वीकार किया है। खास बात यह है कि पिछली रिपोर्ट में भी स्पष्ट किया गया था कि जांच पूरी होने तक नम्रता सिंह को दोषी नहीं माना गया था और उनका प्रमाण पत्र भी रद्द नहीं हुआ था। अब जांच समिति के निष्कर्ष के बाद इस मामले में तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है।

यानी जिस जाति प्रमाण पत्र को लेकर चुनाव के बाद शिकायतें हुईं और जांच की प्रक्रिया शुरू हुई, उसी मामले में उच्च स्तरीय जांच के बाद नम्रता सिंह का गोंड एसटी जाति दावा सही पाया गया है।

अखिलेश के वार पर जयंत चौधरी का संयमित पलटवार

नीरज कुमार दुबे

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का नाम लिए बिना ऐसा तंज कसा है जिसकी गूंज सीधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान तक पहुंच गई। अखिलेश ने कहा, कहां-कहां से आ गए थे, चवत्री का रुपया बना दिया, फिर भी। दरअसल अखिलेश ने अपने इस बयान के जरिये पुराने साथी को राजनीति में आगे बढ़ाने का दावा किया और फिर साथी द्वारा उन्हें छोड़ देने पर अपनी शिकायत दर्ज कराई लेकिन इस दौरान उनके जो तेवर रहे उसने पश्चिमी यूपी की सियासत को गर्मा दिया है। रालोद कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आये हैं और अखिलेश यादव के पुतले फूंक रहे हैं। यही नहीं, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने भी अखिलेश पर पलटवार करते हुए दर्शा दिया है कि एक्शन का रिएक्शन तत्काल होगा। हालांकि अखिलेश के तंज पर जयंत चौधरी ने पलटवार तलखी की बजाय बेहद नपे-तुले अंदाज में किया। उन्होंने कहा, वो अपनी बात कहें तो अच्छा है। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी इस तरह की बयानबाजी से सोचने को मजबूर हो रहे हैं। जयंत ने आगे कहा, लोकतंत्र है, यहां जनता सबको बनाती है और सबको बिगाड़ती है। जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश उन्हें इतना क्यों याद कर रहे हैं, तो उन्होंने गंदे वापस अखिलेश के पाले में डालते हुए कहा, ये तो आप लोग उनसे जाकर पूछिए। दरअसल, यह सिर्फ दो नेताओं की निजी राजनीतिक नोकझोंक नहीं है। इसके पीछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदलते जातीय और गठबंधन समीकरण की पूरी पटकथा पढ़ी जा सकती है। यही बदलाव अखिलेश के मौजूदा हमले को राजनीतिक धार देता है। सपा प्रमुख लगातार पीडीए यानि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश में हैं। पश्चिमी यूपी में उनकी चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि यहां सपा का पारंपरिक मुस्लिम-यादव आधार पूर्वांचल या मध्य यूपी की तरह निर्णायक नहीं रहा है। ऐसे में गुर्जर, दलित, अन्य पिछड़ी जातियों और गैर-जाट मतदाताओं को जोड़ना सपा की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। जयंत चौधरी का रालोद इस गणित में छोटी पार्टी जरूर है, लेकिन पश्चिमी यूपी में उसका प्रभाव उसके चुनावी आंकड़ों से कहीं ज्यादा राजनीतिक वजन रखता है। जाट समुदाय में चौधरी चरण सिंह की विरासत और रालोद की पकड़ अब भी गठबंधन राजनीति के लिए वापस है। भाजपा के साथ जयंत को मौजूदगी एनडीए को पश्चिमी यूपी में जाट समर्थन को साधने का अतिरिक्त आधार देती है। यही कारण है कि अखिलेश का चवत्री वाला तंज मजब पुरानी दोस्ती का हिसाब नहीं, बल्कि नए सामाजिक समीकरणों की गंग भी माना जा रहा है। दलितचस्प यह है कि अखिलेश ने हाल में अपने नेताओं-कार्यकर्ताओं को चुनावी समय में सोच-समझकर बयान देने की नसीहत दी थी, ताकि भाजपा को कोई राजनीतिक लाभ न मिले। इसके तुरंत बाद जयंत पर निशाना साधना बताता है कि सियासी प्राथमिकताएं कभी-कभी रणनीतिक संयम पर भारी पड़ जाती हैं। उधर, जयंत ने तीखा पलटवार करने की बजाय संयम चुना। शायद इसलिए कि वह अखिलेश के बनाए जाट बनाम गैर-जाट नैरेटिव में फंसना नहीं चाहते। उनकी सौम्य प्रतिक्रिया का संदेश भी उतना ही राजनीतिक है। इसका अर्थ यह है कि रालोद अब सपा के साथ नहीं बल्कि एनडीए के साथ ही अपना भविष्य देख रहा है। बहरहाल, चवत्री और रुपया की यह लड़ाई असल में पश्चिमी यूपी की उस सियासी तिजोरी की लड़ाई है, जिसकी चाबी जाट, मुस्लिम, दलित, गुर्जर और अन्य पिछड़े मतदाताओं के हाथ में है।

पुराण दिग्दर्शन

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

ज्ञशुक्रावेकराशिस्थौ सर्वदा वृष्टिदायकौ।

तयोरन्तर्गतो भानुर्नरावृष्टिकरो मतः।।

उदितेऽस्तमिते सौम्ये क्वरे वक्रवत्प्रागते।

चलत्यङ्गारके वृष्टिस्त्रिधा वृष्टिः शनैश्चरे।।

(विष्णुपु २।६।८ कूर्म भविष्येऽपि)

अर्थात् – सूर्य आठ महीने तक वाष्प रूप से जल लेता रहता है, और फिर उसे बरसाता है जिससे अन्न उत्पन्न होते हैं और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। बुध और शुक्र नामक ग्रह जब एक राशि पर निकट निकट रहते हैं तब जल बरसता है और यदि उन दोनों के बीच में सूर्य पड़ जाये तो वृष्टि नहीं होता।

बुध शुक्र और बृहस्पति के उदय तथा अस्त होने के समय, एवं मङ्गल और शनि के वक्त्री (उलटी गति) होने के समय वृष्टि होता है, मङ्गल अतिचार में, और शनैश्च पूर्वोक्त तीनों परिवर्तनों के समय वृष्टि करता है।

यहां हमें यह बताने की आवश्यकता नहीं कि पुराणों ने ऊपर के प्रमाणों में मानसून चलने के समयों को किस खूबी के साथ बताया है। आधुनिक विज्ञानवादियों का कथन है कि शुक्र ग्रह के निकट बादलों के सघन पटल हर वक छाये रहते हैं, ऐसा ही हाल बुध का है। उन दोनों का एक राशि पर होना निस्पन्देह वृष्टि का कारण हो सकता है। भारतीय किसान भी इस वैज्ञानिक बात से भली भाँति परिचित हैं। श्रतएव वे लोग चतुर्मास में – बुध शुक्र का मेल पूछा करते हैं।

दक्षिणोत्तर अयन

सूर्य की विशेष गति से ही दिन रात का ह्रास और वर्द्धन होता है। इसी प्रकार गर्मी और सर्दी का कारण भी सूर्य का विशेष संस्थाना ही है। पृथ्वी पर जब सूर्य को किरणें तिरछी पड़ती हैं तब सर्दी हो जाती है, और जब सीधी पड़ती हैं तब गर्मी हो जाती है।

क्रमशः ...



ज्ञान/मीमांसा

‘दिमागी नक्सल’ नरेटिव बदलने की नई सियासी फिरकी तो नहीं?

अजय बोंकिल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त पर लाल किले से अपने 13वें भाषण में नए शब्द ‘दिमागी नक्सल’ का जिक्र कर देश में एक नई राजनीतिक और बौद्धिक बहस को हवा दे दी है। सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री ने यह जुमला किसके लिए और क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि ‘अर्बन नक्सल’ तो पहले से चलन में था। तो क्या ‘दिमागी नक्सल’ उसके आगे की और कोई अदृश्य चीज है? या फिर यह विपक्ष और जेन-जी के हावी होते मुद्दों से ध्यान हटाने की नई राजनीतिक फिरकी है?

‘दिमागी नक्सल’ कहकर प्रधानमंत्री किस पर निशाना साध रहे थे और किन तत्वों से देश को आगाह कर रहे थे? इसको लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है। लोग अपने नरेटिव के हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में खास तौर से कहा कि ‘दिमागी नक्सल’ वो लोग हैं, जो कहीं न कहीं समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। जो शायद विकसित भारत के निर्माण को नहीं देख सकते।

दिमागी नक्सली विचारधारा वाले लोग समाज को गलत रास्ते पर ले जाने का मौका तलाश रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ऐसे लोगों को ‘पहचानने’ और ‘अलग थलग’ करने की अपील की। हालांकि प्रधानमंत्री ने ‘दिमागी नक्सल’ के रूप में किसी व्यक्ति अथवा संगठन विशेष का नाम नहीं लिया। फिर भी मानो दाढ़ी में छिपा तिनका खुद ही बोल उठा कि मैं यहां हूँ।

अब सवाल यह कि अगर पीएम सीधे किसी पर वार नहीं कर रहे थे तो उनके इस जुमले का असल राजनीतिक मकसद क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हाल में जेन-जी और उसके पहले चले सरकार विरोधी आंदोलनों और सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे एंटी मोदी नरेटिव से ध्यान हटाने के लिए ‘दिमागी नक्सल’ का नया शोशा उछाला गया है?

अगर ऐसा है तो यह कारगर होता दिख रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग अब दूसरे बुनियादी सवालों से हटकर ‘दिमागी नक्सल’ पर ही लामबंद होते दिख रहे हैं। इस बीच सीजेपी की तर्ज पर दिमागी नक्सल जनता पार्टी नामक व्यंग्यात्मक वर्चुअल पार्टी भी सोशल मीडिया पर बन गई है, जिससे करीब 2 लाख लोग जुड़ गए हैं।

जाहिर है यह बहस अभी और चलेगी, जब



तक कि यह तय न हो जाए कि इस तीर का असली लक्ष्य कौन है और वो कहां तक निशाने पर लगा है? बहत्तों का मानना है कि प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण की सुखी ‘दिमागी नक्सल’ ही थी।

प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद और माओवाद के खिलाफ अपनी सरकार की निर्णायक कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा था कि हमने ‘हथियारी नक्सलियों’ को तो खत्म कर दिया कि लेकिन उनके वैचारिक पोषक और समर्थक ‘दिमागी नक्सली’ व्यवस्था में घुसपैठ कर नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यह बात देश के गृहमंत्री अमित शाह के उस दावे के संदर्भ में कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में हिंसक नक्सलवाद अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।

नक्सल शब्द की पश्चिम बंगाल में आज से करीब साठ साल पहले नक्सलबाड़ी गांव में जमींदारों के शोषण और अत्याचार तथा पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ वामपंथियों के एक वर्ग द्वारा संगठित किसानों मजदुरो के हिंसक विद्रोह के साथ शुरू हुई थी। यह बगावत इस विचार से प्रेरित थी कि देश में राजनीतिक-सामाजिक क्रांति बंदूक की नली से आ सकती है।

यह पूंजीवादी शोषक व्यवस्था के खिलाफ खुला और हिंसक विद्रोह था। हालांकि न तो व्यवस्था बदली और न ही शोषण खत्म हुआ। अलबता लंबे समय तक रक्तपात जरूर चलता रहा। यही नहीं, जिन देशों में इस तरह की सफल क्रांति हुई, उसमें से अधिकांश इस सिद्धांत से किनारा कर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पूंजीवाद

की गोद में बैठ चुके हैं।

यहां सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर दिमागी नक्सल कहा किसे? क्या यह केवल देश में हिंसक क्रांति के समर्थक दिमागों के बाकी बचे अवशेषों के लिए कहा गया अथवा इसके दायरे में वो सभी लोग हैं, जो मोदी, भाजपा और संघ से अहसमत हैं, या फिर वो तमाम लोग और खासकर जेन जी भी है, जो किसी खास राजनीतिक विचारधारा के समर्थक न होकर केवल अपने हकों की मांग कर रही है? और सियासी पार्टियां उन्हें पीछे से समर्थन दे रही हैं।

कुछ विरोधियों का यह भी कहना है कि संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पारित करने में नाकाम रही सरकार अब ‘दिमागी नक्सल’ का नया शაूपा लेकर आई है।

अगर असहमति और न्याय मांगना ही ‘दिमागी नक्सल’ होना है तो फिर झारखंड या बिहार में न्याय मांगने वाले छात्र क्या हैं? उसी तरह अगर बंदूक के जरिए ही सामाजिक-राजनीतिक न्याय की प्राप्ति संभव होती तो इस देश में क्रांति कब की आ जाती? लेकिन यह देश मूलतः गांधी के रास्ते पर चलने और उसे ही संघर्ष का स्वाभाविक और बहुमान्य स्वरूप मानने वाला देश है।

हालांकि इसके लेकर भी असमतियां रही हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। इसी सत्ता परिवर्तन भी वोट के जरिए हो, यह सर्व स्वीकार्य है।

जहां तक ‘दिमागी नक्सल’ की व्याख्या की बात है तो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु मिश्रा ने कहा कि दिमागी नक्सल ‘गांधीयन्स विद गन्स’ है। यानी बंदूकधारी गांधीवादी। यह अपने आप में ही विरोधाभासी है। गांधी के साथ लाठी तो हो सकती है, गन कैसे हो सकती है। सुधांशु शायद यह कहना चाहते हैं कि दिमागी नक्सल ‘प्रच्छन्न गांधीवादी’ हैं।

जो बात तो गांधी की करते हैं, लेकिन हिंसा के जरिए देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। किसी भी मुद्दे और आंदोलन का इसका माध्यम बनाने की कोशिश की जाती है। मोदी सरकार की नीतियों

और कानूनों आदि की गलत अथवा अर्द्धसत्यात्मक व्याख्या की जाती है।

‘दिमागी नक्सल’ से खुद को जोड़ने वाली पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता और देश के पूर्व गृहमंत्री रहे पी. चिदम्बरम् की तरफ से आई। उन्होंने कहा कि मुझे अपने ‘दिमागी नक्सल’ होने पर गर्व है। इस पर एक प्रतिक्रिया यह भी आई कि ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का पहली बार प्रयोग तो चिदम्बरम ने ही 2010 में किया था, जैसे कि ‘हिंदू आतंकवाद’ यानी मोदी ने तो उसे आज के संदर्भ में दोहराया भर है। इसी तरह आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं भी दिमागी नक्सली हूँ, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ।

वैसे ज्यादातर विपक्षी नेताओं का मानना है कि बात भले ही दिमागी नक्सली की हो, असल में इसकी आड़ में हर सरकार विरोधी स्वर को दबाने की चाल है। माकपा महासचिव एम. ए. बेबी ने कहा कि उनकी पार्टी नक्सलवाद का विरोध करती है, लेकिन सरकार द्वारा माओवादियों से निपटने में कानून और संविधान का उल्लंघन करने के भी खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि नक्सलवाद एक राजनीतिक दृष्टिकोण और विचारधारा है, जिससे हम सभी पूरी तरह अहसमत हैं। बेबी के मुताबिक यह कहना कि उनके दिमाग में माओवादी विचार हैं, एक सुविधाजनक और बेहद आपत्तिजनक आरोप है।

इसमें दो राय नहीं कि व्यवस्था से नाराज और परेशान हर व्यक्ति ‘दिमागी नक्सल’ तो नहीं हो सकता। फिर नक्सल होने के लिए भी ‘दिमाग’ की दरकार तो है। भले ही खुरपाफाती क्यों न हो। वरना यह शब्द ही नहीं बनता। इसके पहले प्रचलित ‘अर्बन नक्सल’ में ऐसी कोई प्री-कंडीशन नहीं थी।

विपक्ष को आशंका है कि ‘दिमागी नक्सल’ की आड़ में सरकार हर उस शख्स को दबोच सकती है, जो सवाल करे, सरकार की नीतियों और मंशा पर उंगली उठाए। व्यवहार में ऐसा होगा या नहीं, होगा तो किस हद तक होगा, इस बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। थोड़े बहुत ‘दिमागी नक्सल’ समूचे देश के मानस को नहीं बदल सकते।

बहरहाल देश में मोदी के भाषण के बाद नया दिमागी नरेटिव वॉर शुरू हो चुका है, जिसमें हर कोई अपनी सुविधा और पूर्वाग्रह के साथ तलवार भांज रहा है। इसका अंजाम देखने के लिए हमें रुकना होगा।

उस्ताद बिस्मिल्ला खान

विश्वविद्यालय और शांतिनिकेतन से अपनी शिक्षा पूरी की थी। शहनाई वादन बिस्मिल्ला खां साहब को विरासत में मिला था। दरअसल, उनके परिवार के लोगों को शुरूआत से ही राग दरबारी बजाने में महारत हासिल थी।

हर साल स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण के बाद आज भी बिस्मिल्ला खां की शहनाई की गूंज सुनाई देती है। यह परंपरा देश के पहले पीएम जवाहर लाल नेहरू से समय से चली आ रही है। इसके अलावा दर्शन और आकाशवाणी की सिन्नेचर द्यून में भी बिस्मिल्ला खां की शहनाई सुनाई देती है।



पद्म भूषण और साल 1980 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा साल 1930 में बिस्मिल्ला खां को ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला था। एमपी सरकार ने सर्वोच्च संगीत पुरस्कार %ताम्रसैन% की पदवी से बिस्मिल्ला खां को सम्मानित किया था।

महज 14 साल की उम्र में प्रयागराज में संगीत परिषद में बिस्मिल्ला खां ने अपनी शहनाई से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। साल 2001 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इससे पहले साल 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, साल 1968 में

पद्म भूषण और साल 1980 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा साल 1930 में बिस्मिल्ला खां को ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला था। एमपी सरकार ने सर्वोच्च संगीत पुरस्कार %ताम्रसैन% की पदवी से बिस्मिल्ला खां को सम्मानित किया था।

उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को संगीत की लोकधुनें बजाने में महारत हासिल थी। इनमें से झुला, बजरी, चैती जैसी कठिन औरनी शहनाई से सबको के लिए बिस्मिल्ला खां ने कठोर तपस्या की थी। इसके साथ ही उन्होंने क्लासिकल और मौसिकी में भी शहनाई को सम्मान दिलाया था। उन्होंने अपनी काबिलियत से शहनाई को संगीत के शिखर पर पहुंचाया था। शांतिनिकेतन और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उनको डॉक्ट्रेट की उपाधि से नवाजा गया था।

वह अपना सारा पैसा परिवार और जरूरतमंदों पर खर्च कर देते थे। जिस कारण बाद में उनको आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा था। तब सरकार ने आगे आकर बिस्मिल्ला खां की मदद की थी। वहीं 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्ला खां का निधन हो गया था।

अल्पसंख्यकों की असुरक्षा से आतंकवाद तक पाक का यथार्थ

ललित गर्ग



नागरिकता का आधार नहीं बनाया। संविधान ने हर नागरिक को समान नागरिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और अपनी आस्था के पालन की स्वतंत्रता दी। भारत में मुसलमानों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका, सेना, शिक्षा, उद्योग, कला, खेल और प्रशासन सहित जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति है। इसके विपरीत पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की रिपोर्टें गंभीर प्रश्न उठाती हैं। भूमन राष्ट्रसंघ वाच की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में ईशनिंदा कानूनों के दुरुपयोग ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को हिंसा, मनमानी गिरफ्तारी और सामाजिक दबाव के प्रति अत्यंत संवेदनशील बना दिया है। रिपोर्ट में हिंदुओं, ईसाइयों और अहमदियों सहित अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और जबरन विवाह-धर्मांतरण जैसी समस्याओं का उल्लेख है। भारत में सरकारों के खिलाफ मुसलमानों एवं अन्य अल्पसंख्यकों के द्वारा आवाज उठाई जा सकती है, न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। यही लोकतांत्रिक भारत और धार्मिक-सामुदायिक असुरक्षा से जुझते पाकिस्तान के बीच बुनियादी अंतर है। दूसरा बड़ा प्रश्न पाकिस्तान के भारत-विरोधी आतंकवाद का है। पिछले कई दशकों में सीमा पार आतंकवाद भारत की सुरक्षा के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में

रहा है। संसद पर हमला, मुंबई हमले, पठानकोट, उरी, पुलवामा और जम्मू-कश्मीर में लगातार हिंसक घटनाएं इस समस्या का हिस्सा रही हैं। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर कार्रवाई की। विदेश मंत्रालय ने उस समय स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान की जमीन पर चल रहे आतंकवादी ढांचे के विरुद्ध कार्रवाई की गई क्योंकि पाकिस्तान उन्हें नष्ट करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा था। 2025 में पहलगांव के आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सुरक्षा नीति में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत दिया।

22 अप्रैल 2025 के हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू-कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत सरकार ने इसे आतंकवादी ढांचे के विरुद्ध लक्षित और नियंत्रित कार्रवाई बताया। यह परिवर्तन केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है। भारत ने आतंकवाद के साथ-साथ उसके वित्तीय और नशीले पदार्थों के नेटवर्क पर भी ध्यान केंद्रित किया है। सरकार ने विदेशी तत्वों द्वारा नशीले पदार्थों को सीमा पार भेजकर ‘नाकों-ट्रैर’ को वित्त उपलब्ध कराने की बात कही है। यहां भारत की चुनौती केवल सीमा पर बंदूक लेकर खड़े आतंकवादी से नहीं है। चुनौती उस पूरे तंत्र से है जिसमें आतंकवाद, हथियार, ड्रोन, नशीले पदार्थ, फसमें सूचनाएं और सामाजिक विभाजन-सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। पिछले एक दशक से अधिक समय में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि उसने पाकिस्तान को यह संदेश दिया है कि आतंकवाद और बातचीत को समानांतर रास्तों पर नहीं चलाया जा सकता। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट कार्रवाई और 2025 का ऑपरेशन सिंदूर अलग-अलग घटनाएं जरूर हैं, लेकिन इनके पीछे एक समान संदेश दिखाई देता है- भारत अतंकवाद को केवल सहने या निंदा करने तक सीमित नहीं रहेगा। इस बदले हुए भारत की

तस्वीर पाकिस्तान की बेचैनी को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत की अर्थव्यवस्था, तकनीकी क्षमता, अंतरिक्ष कार्यक्रम, रक्षा उत्पादन, डिजिटल बुनियादी ढांचा, वैश्विक कूटनीति और रणनीतिक प्रभाव लगातार बढ़े हैं। आज भारत को विश्व राजनीति में केवल दक्षिण एशिया की शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक निर्णय-प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा जाता है। पाकिस्तान की समस्या केवल यह नहीं है कि भारत उससे आर्थिक और सामरिक रूप से आगे निकल रहा है, उसकी बड़ी समस्या यह है कि भारत अपनी बहुलतावादी लोकतांत्रिक पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है।

जरदारी का बयान इसलिए भी विचारणीय है कि पाकिस्तान को भारत के भीतर की विविधता पर टिप्पणी करने से पहले अपने घर के भीतर झांकना चाहिए। भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ती आबादी का तथ्य स्वयं बताता है कि भारत में मुस्लिम समुदाय का अस्तित्व, विस्तार और सामाजिक जीवन किसी ‘समाप्ति’ की कहानी नहीं है। दूसरी ओर पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर आज भी अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं गंभीर चिंता व्यक्त कर रही हैं। इसलिए दुनिया के उन देशों को भी पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए, जो केवल रणनीतिक या राजनीतिक हितों के कारण उसकी हर बात का समर्थन करते हैं। किसी राष्ट्र का मूल्यांकन उसके भाषणों से नहीं, उसके व्यवहार से होना चाहिए। यदि कोई देश एक तरफ आतंकवाद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिबद्धता जताए और दूसरी तरफ उसकी धरती से सक्रिय आतंकी नेटवर्क लगातार पड़ोसी को निशाना बनाते रहें, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को केवल शून्यीतिक शब्दों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। भारत की शक्ति का अर्थ किसी धर्म या देश के प्रति घृणा नहीं, बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई है। भारत के मुसलमान भी उनसे ही भारतीय हैं जितने हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और अन्य समुदाय।

आज का इतिहास

- 1790 जनरल मेडोस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने डिंडिगुल पर कब्ज़ा जमाया।
- 1915 पहले विश्व युद्ध के दौरान इटली ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
- 1959 हवाई अमेरिका का 50वां प्रांत बना।
- 1965 यूरोपीय देश रोमानिया में संविधान को अंगीकार किया गया।
- 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संसद में पारित।
- 1972 भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित।
- 1997 पूर्वी चीन में चक्रवाती तूफान विन्की से 140 लोगों की मौत हुई और तीन हजार लोग घायल हुए।
- 1983 फिलीपींस के विपक्षी नेता बेंनिग्रो एस. एक्त्रिनो की स्वैच्छिक निर्वासन के पश्चात् वापसी, भूमि पर क़दम रखते ही गोली मारकर उनकी हत्या।
- 1988 भारत नेपाल सीमा पर आये तीव्र भूकंप से एक हज़ार लोगों की मौत।
- 1991 संविधत संघ में राष्ट्रपति गोर्बाचोव अपदस्थ, मास्को में कर्फ्यू, क्रान्ति विफल एवं गोर्बाचोव पुनः सत्ता में।
- 1993 राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने रूसी संसद भंग किया।
- 2000 दक्षिण-पूर्वी आर्देक प्रान्त में लगी आग से 1600 हेक्टेयर क्षेत्र में खड़े वन नष्ट, रूसी पनडुब्बी के सभी 118 सदस्यों के मारे जाने की पुष्टि।
- 2003 संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफ़ी अन्नान ने इराक में संयुक्त शांति सेना भेजने का प्रस्ताव खारिज किया।
- 2005 बांग्लादेश और भारत की सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच संघर्ष विराम का समझौता सम्पन्न।
- 2006 इराक के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने नरसंहार ट्रायल में भाग लेने से इन्कार किया।
- 2008 श्रीनगर और पाक अधीकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के बीच चलने वाली कारवां-ए-अमन बस सेवा पुनः प्रारम्भ।
- 2008 मून मिशन पर भारत ने नासा से हाथ मिलाया।
- 2009 भारतीय नौसेना का लड़ाकू विमान 'सी हेरियर' गोवा से उड़ान भरने के पश्चात् अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान चालक ले. कमाण्डर सौरभ सक्सेना का निधन।
- 2012 अफ़्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो में इबोला वायरस के संक्रमण से 20 लोगों की जार्ने गई।
- 2013 मलेशिया में चिन स्वी मंदिर के समीप बस हादसे में 37 लोग मारे गए और 16 घायल लोग हुए।
- 2014 राफा में इज़रायली हवाई हमले में हमसल के तीन शीर्ष कमांडर मारे गए।

वंदेमातरम क्यों बना राजनीतिक विवाद का विषय?

सौरभ वार्ण्य

वंदेमातरम केवल दो शब्दों का उच्चारण नहीं है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों, राष्ट्रभक्ति की भावना और उस दौर के संघर्ष का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसके गायन से देशभक्ति से वातावरण भी गुंजायमान हो जाता है। जिस गीत ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीयों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चेतना जगाने में भूमिका निभाई, वह आज राजनीतिक बहस और विवाद का विषय बन गया है। सवाल यह नहीं है कि वंदेमातरम् का सम्मान होना चाहिए या नहीं—उसका सम्मान भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निर्विवाद रूप से होना चाहिए। असली सवाल यह है कि आखिर एक राष्ट्रीय भावना से जुड़े गीत को बार-बार राजनीतिक विवाद के केंद्र में क्यों खड़ा कर दिया जाता है? अभी 15 अगस्त को कांग्रेस के कार्यालय में फिर से इसको लेकर विरोधियों ने राजनीतिक तुफान खड़ा कर दिया। यानी देशभक्ति को भी तराजू में तोला जा रहा है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह सह नहीं है। आज देश 80 वां स्वतंत्रता दिवस मना चुका है। आगामी दिवस जब 21 साल बाद देश 100 वां स्वतंत्रता दिवस मनायेगा तब भी हम देश को उंचाइयों पर ले जाने की जगह यह विवाद कर रहे होंगे। आज के राजनेताओं को दो देश के लिए कुछ सोचना होगा।

भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी विविधता है। यहां अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और विचारधाराएं सदियों से साथ-साथ रही हैं। स्वतंत्रता आंदोलन ने भी इसी विविधता को एक साझा राष्ट्रीय उद्देश्य में जोड़ने का काम किया था। वंदेमातरम् उसी दौर की राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण स्वर

था। इसलिए जब इसे राजनीतिक बयानबाजी का हथियार बनाया जाता है, तो केवल एक गीत पर विवाद नहीं होता, बल्कि उस व्यापक राष्ट्रीय भावना पर बहस खड़ी हो जाती है, जिसने देश को स्वतंत्रता के संघर्ष में एकजुट किया था।

वंदेमातरम् की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत उन्नीसवीं सदी के अंतिम दौर में सामने आया। बाद में यह स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीय चेतना का महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे उत्साह और संघर्ष की भावना के साथ अपनाया। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलनों में इसके उद्घोष ने लोगों में राष्ट्रीय भावना पैदा की। यही कारण है कि वंदेमातरम् को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है।

लेकिन इतिहास के साथ-साथ उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भी समझना होगा। भारत एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज था। राष्ट्रवादी आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए यह आवश्यक था कि देश के सभी समुदायों को उसमें बराबर का स्थान महसूस हो। वंदेमातरम् के कुछ अंशों की धार्मिक प्रतीकात्मकता को लेकर समय-समय पर आपत्तियां भी सामने आईं। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने 1937 में यह निर्णय लिया कि सार्वजनिक अवसरों पर गीत के शुरुआती दो पदों का उपयोग किया जाए, जिन्हें अपेक्षाकृत अधिक स्वीकार्य माना गया। यह निर्णय बताता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व ने भी राष्ट्रीय एकता और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया था।

स्वतंत्र भारत में भी वंदेमातरम् को विशेष सम्मान मिला। संविधान सभा ने 24 जनवरी



1950 को इसे राष्ट्रगान के समान सम्मान देने की बात स्वीकार की। वहीं 'जन गण मन' को राष्ट्रगान और वंदेमातरम् को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। यानी भारत के संवैधानिक और राष्ट्रीय जीवन में दोनों की अपनी विशिष्ट पहचान बनी। समस्या तब पैदा होती है, जब इस ऐतिहासिक संतुलन को राजनीतिक बहस में बदलकर यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि कौन अधिक राष्ट्रवादी है और कौन कम।

राष्ट्रभक्ति किसी एक गीत, नारे या प्रतीक तक सीमित नहीं हो सकती। देश के प्रति सम्मान का अर्थ संविधान के प्रति निष्ठा, कानून का सम्मान, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, कर्तव्यों का पालन और राष्ट्रभक्तों में ईमानदार योगदान भी है। यदि कोई व्यक्ति वंदेमातरम् का सम्मान करता है तो यह उसकी राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति की राष्ट्रभक्ति को केवल इस आधार पर मापना कि वह किसी विशेष अवसर पर किस तरह का नारा लगाता है, लोकतांत्रिक समाज के लिए स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर, यह भी सही है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना समाज में बनी रहनी चाहिए। किसी राष्ट्रीय गीत या स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रतीक का जानबूझकर अपमान करना भी उचित नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी

भी है। इसलिए वंदेमातरम् के सम्मान और उसके राजनीतिक दुरुपयोग—दोनों के बीच स्पष्ट अंतर करना होगा।

आज राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे इतिहास को समझें, उसे चुनावी हथियार न बनाएं। वंदेमातरम् पर बहस यदि इतिहास, साहित्य, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में हो तो वह सार्थक हो सकती है। लेकिन यदि इसका इस्तेमाल विरोधी दल या किसी समुदाय को राष्ट्रविरोधी साबित करने के लिए किया जाए तो यह बहस समाज को जोड़ने के बजाय विभाजित करेगी।

यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है—क्या राष्ट्रवाद का अर्थ केवल भावनात्मक नारों तक सीमित हो जाना चाहिए? यदि देश में बेरोजगारी है, किसान अपनी आय को लेकर चिंतित है, युवा बेहतर शिक्षा और रोजगार की तलाश में है, सीमाओं की सुरक्षा चुनौतीपूर्ण है, शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है और गरीब व्यक्ति सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए काम करना भी राष्ट्रभक्ति है।

सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करता है, किसान खेत में अन्न पैदा करता है, शिक्षक नई पीढ़ी तैयार करता है, वैज्ञानिक अनुसंधान करता है और श्रमिक अपने श्रम से अर्थव्यवस्था को गति देता है। इन सभी के योगदान में राष्ट्रभक्ति दिखाई देती है।

दुर्भाग्य से हमारी राजनीतिक बहस में कई बार वास्तविक मुद्दों की जगह प्रतीकों को केंद्र में लाने की प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई देती है। प्रतीकों की अपनी भूमिका है, लेकिन प्रतीक तभी सार्थक होते हैं जब उनके पीछे भावना और जिम्मेदारी को भी समझा जाए।

सरकार को जंतर-मंतर छात्र आंदोलन से सबक लेना चाहिए

विपिन पबी

दिल्ली पुलिस ने इस बात से इंकार किया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सी.जे.पी.) के नेतृत्व वाले मार्च के दौरान अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया था। पुलिस का कहना है कि उसके अधिकारियों ने बल का प्रयोग केवल तभी किया, जब प्रदर्शनकारियों ने 'हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया'। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में, दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया है कि 20 जुलाई को संसद तक मार्च के दौरान सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों को 'भौड़-निधंत्रण उपाय' के रूप में और 'विरोध प्रदर्शन में परेशान किए जा रहे किसी भी व्यक्ति की मदद करने' के लिए तैनात किया गया था। दुर्भाग्य से पुलिस के लिए, विरोध स्थल की परिस्थितियां अतीत के ऐसे विरोध प्रदर्शनों से बिल्कुल अलग थीं, जिसका एक महत्वपूर्ण कारण था। जहां अतीत में बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शनों में बमुश्किल एक दर्जन कैमरे होते थे, जिनमें से अधिकांश समाचार फोटोग्राफरों के होते थे, जो 'कार्रवाई' का केवल एक छोट्टा-सा हिस्सा ही कैद कर पाते थे और वह भी पुलिस कर्मियों के पीछे से, वहीं इस बार के विरोध प्रदर्शन को हजारों (मोबाइल) कैमरों द्वारा कैद किया गया और वह भी 'रणक्षेत्र' के अंदर से। इसने कार्रवाई को लगभग सभी कोणों से कवर करने में मदद की। इंटरनेट पर उपलब्ध सैंकड़ों वीडियो और तस्वीरें पुलिस की ज्यादतियों को दर्शाती हैं, जिनमें महिलाओं का यौन उत्पीड़न और उन छात्रों का पीछा करना और पीटना

शामिल है, जो या तो भाग रहे थे या ड़्क़शा की किसी भी कार्रवाई में शामिल नहीं थे। यह भी एक तथ्य है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस कर्मियों को मारा, जिससे उनमें से 200 से अधिक को मामूली चोटें आईं, जो समान रूप से निंदनीय है। पुलिस अब इस दावे के साथ भी सामने आई है कि कोई पैलेट गन नहीं चलाई गई थी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उनके दावों का समर्थन किया है, हालांकि इसके विपरीत साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। यह दलील भी अब सामने आई है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले छात्र विरोध स्थल पर घुस गए थे और पुलिस ने आग्रह किया है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ दर्ज 2500 से अधिक प्राथमिकियां (एफ.आई.आर.) वापस नहीं ली जानी चाहिए। विडंबना यह है कि जिस दिन अखबारों में इस दलील की खबर छपी, उसी दिन एक और रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि सरकार ने एक अन्य मामले के जवाब में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि 28 राज्यों में से 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर वर्तमान में आपराधिक मामले चल रहे हैं। इनमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी शामिल हैं, अकेले जिन पर ऐसे 29 मामले चल रहे हैं। कुल मिलाकर देश भर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4192 आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 514 मामले एक दशक से लंबित हैं। विरोध प्रदर्शन को संभालने में अक्षमता स्पष्ट रूप से सरकार और पुलिस द्वारा निर्णय लेने में हुई एक चुक थी। सरकार ने, जैसा कि उसकी आदत है, प्रदर्शन स्थल पर छात्रों की संख्या बढ़ने के बावजूद उनसे संपर्क नहीं किया। उन्हें थका देने की उसकी रणनीति विफल रही।

हिंदुओं को किसी तरह सहन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुसलमान

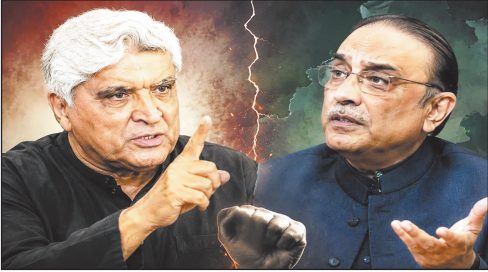
नीरज कुमार दुबे

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपने ही देश की हिंदू आबादी को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की स्थिति और वहां की तथाकथित धार्मिक सहिष्णुता के दावों पर फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हम आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़े एक कार्यक्रम में जरदारी ने भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हुए पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। सबसे सख्त पलटवार मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने किया है।

जरदारी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को लेकर दोनों देशों का नजरिया अलग है। उन्होंने कहा कि भारत अखंड भारत की सोच रखता है, जबकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की हिंदू आबादी का जिक्र करते हुए कहा कि वहां मुसलमान 3-4 प्रतिशत हिंदू आबादी को टॉलरेट यानी सहन करते हैं। जरदारी ने यह दावा भी किया कि पाकिस्तान में हिंदू उतने ही स्वतंत्र और सुरक्षित हैं, जितने वे कहीं और हो सकते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान के हिंदू भारत की बजाय पाकिस्तान के साथ रहना ज्यादा पसंद करेंगे।

देखा जाये तो यहीं जरदारी के बयान की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। जिस देश के राष्ट्रपति को अपने नागरिकों की बराबरी, सुरक्षा और सम्मान की बात करनी चाहिए, वही राष्ट्रपति अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हम उन्हें सहते हैं जैसी भाषा इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है। देखा जाये तो सवाल सिर्फ एक शब्द का नहीं है। सवाल उस मानसिकता का है जिसमें किसी देश के नागरिकों के अधिकारों को उनके धर्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय की सहनशीलता से जोड़ दिया जाता है।

जरदारी का बयान इसलिए भी निशाने पर है क्योंकि



उनके आधिकारिक बयानों में पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने वाला देश बताया जाता रहा है। अगस्त 2025 में अल्पसंख्यक दिवस के मौके पर जरदारी ने संविधान के तहत सभी नागरिकों को समान अधिकार देने, धार्मिक भेदभाव के खिलाफ खड़े होने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की प्रतिबद्धता जताई थी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि संवैधानिक बराबरी और सार्वजनिक मंच पर हम हिंदुओं को सहते हैं, इन दोनों में से पाकिस्तान की असली सोच कौन-सी है?

दूसरी ओर, जरदारी के बयान पर जावेद अख्तर ने बिना किसी लाग-लपेट के सीधा हमला किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऊपर पर लिखा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कहते हैं कि उनके देश में 3-4 प्रतिशत हिंदू आबादी को टॉलरेट किया जाता है। इसके बाद अख्तर ने जरदारी के पुराने चर्चित उपनाम 'Mr Ten Percent' को पकड़ते हुए ऐसा तर्ज का सामना किया, जिसने पूरे बयान को और ज्यादा राजनीतिक रूप से विस्फोटक बना दिया।

जावेद अख्तर ने कहा कि वह समझ सकते हैं कि जरदारी हमेशा से उन लोगों के प्रति असंवेदनशील रहे हैं जो 10 प्रतिशत से कम हैं। यह एक सीधा और बेहद धारदार व्यंग्य था। जरदारी के 'Mr Ten Percent' उपनाम को उनके हिंदुओं के 3-4 प्रतिशत वाले बयान से जोड़कर अख्तर ने एक ही बार में उनकी संवेदनशीलता और नैतिकता दोनों पर सवाल खड़ा कर दिया।

राजेश बादल

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत एक के बाद एक निमंत्रण भेज रहा है लेकिन वे रुठे हुए हैं। भारत अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों और कूटनीति की परंपराओं का पालन करते हुए उन्हें आमंत्रित करता आ रहा है। जब वे प्रधानमंत्री बने तो पहला आमंत्रण भारत ने ही भेजा था। लेकिन वे ठुकराकर मलेशिया और चीन चले गए। इसके बाद भी भारत के प्रयास जारी रहे। आगामी 12-13 सितंबर को भारत में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हो रहा है। हालांकि बांग्लादेश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, फिर भी सदस्यता दिखाते हुए भारत ने स्वाभाविक न्यौता अपने इस पड़ोसी को भेजा।

लेकिन बांग्लादेश अपनी दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तारिक रहमान पारिवारिक रंजिश या प्रतिद्वंद्विता को प्राथमिकता दे रहे हैं। वैदेशिक संबंधों की पेचीदगियां समझने में उन्हें वक्त लगेगा। उनका हट है कि भारत शेख हसीना वाजेद को उल्टा सौंप दे। भारत इसके लिए बाध्य नहीं है। यूं तो दलाई लामों को दशकों से चीन मांग रहा है, पर उसके साथ कूटनीतिक रास्ते बंद नहीं हैं। यह बात बांग्लादेश को आज नहीं तो कल समझनी ही पड़ेगी। तारिक को पारिवारिक अतीत भूलना होगा। दरअसल बांग्लादेश की स्थापना के बाद से वहां का घटनाक्रम समझना होगा क्योंकि 58 साल के प्रधानमंत्री तारिक रहमान मुल्क को उसी राह पर ले जा रहे हैं, जिस पर कभी उनके पिता जियाउर्रहमान ले गए थे। उनके पिता ने पहले दो युद्धों में पाकिस्तान की ओर से भारत के विरुद्ध हिस्सा लिया।

लेकिन जब बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करने के लिए शेख मुजीबुर्रहमान ने संघर्ष छेड़ा तो वे अमनमे होकर पाकिस्तानी फौज का साथ दे रहे थे। जब पाकिस्तानी सेना के अत्याचार बढ़ते गए तो वे पाला बदलकर शेख मुजीब के साथ आ गए। बंगबंधु शेख मुजीब की गिरफ्तारी के बाद जनरल जियाउर्रहमान ही थे, जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी का ऐलान ढाका रेडियो से किया



था।

बांग्लादेश की अवाम इस ऐलान के बाद जनरल जिया पर भरोसा करने लगी थी। वह नहीं समझ सकी कि जनरल जिया के भीतर एक महत्वाकांक्षी फौजी पल रहा है और वह नए बांग्लादेश का सुप्रीमो बनना चाहता है। जिया को कतई उम्मीद नहीं थी कि शेख मुजीब कभी जिंदा लौटेंगे और देश के पितृपुरुष बन जाएंगे। शेख मुजीब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश की नींव डाली।

जिस देश का नाम ही बांग्ला भाषा के आधार पर पड़ा हो तो स्पष्ट है कि इस्लाम का वहां वह रूप नहीं था, जो पाकिस्तान में था। पाकिस्तान अपने दूसरे हिस्से से नफरत करता था तो उसका मूल कारण यही था। इस पृष्ठभूमि में कह सकते हैं कि जनरल जियाउर्रहमान उचित अवसर की तलाश में थे, जब वे शेख मुजीब को हटा सकते थे।

मिजाज से वे कट्टरपंथी थे और धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। परदे के पीछे अपने मकसद में उन्हें चार साल लगे। जब 1975 में सैनिक विद्रोह हुआ और शेख मुजीब कुन्बे के साथ मारे गए तो बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक धारा और भारत के प्रति मैत्री भावना की भी हत्या हो गई। जनरल जियाउर्रहमान राष्ट्रपति बने तो भारत से दूरी और चीन से निकटता उनकी विदेश नीति की प्राथमिकताएं थीं। धर्मनिरपेक्षता की राह त्यागकर बांग्लादेश सांप्रदायिक और इस्लामी मुल्क बनने जा रहा था। यह अलग बात थी कि जियाउर्रहमान ने विकास की रफ्तार तेज की और दुनिया के

प्रवीण बांसल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में देशहित, समाजहित में चल रहे अनेक कल्याणकारी कार्यों और योजनाओं का जिक्र किया। वहीं विश्व की घटनाओं और आने वाली चुनौतियों का जिक्र भी किया। इसी के साथ उन्होंने नए तकनीकी और डिजिटल युग में नैरेटिव गढ़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग दृत्स को लेकर देशवासियों को सचेत भी किया। इसके लिए उन्होंने 'दिमागी नक्सली' शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि आज की लड़ाई जमीन पर नहीं, दिमाग से लड़ी जाती है।

इस शब्द के विरोध में विपक्षी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सली होने पर गर्व महसूस किया। यहां 'चोर की दाढ़ी में तिनका' वाली कहावत पूरी तरह फिट बैठती है। ऐसा लगा जैसे यह शब्द, कांग्रेस और उसकी पूर्ववत कार्यशैली का पर्यायवाची है और यह सीधे उन पर कहा गया हो। सच कड़वा होता है। प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन जिन्होंने बिना हथियारों के आज तक देश में वैमनस्क, विरोध, जहर और भेदभाव फैलाने का काम किया, उन्हें लगा कि यह उंगली उन्हीं की तरफ उठी है।

कांग्रेस ने सत्ता में बने रहने के लिए हमेशा आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा दिया है। आतंकवाद हिंदुओं के खिलाफ हो तो उसको नजरअंदाज किया। हजारों हिंदुओं के कत्ल और उनके भगाने का कश्मीर सबसे बड़ा उदाहरण है। उनको शासनकाल में इस्लामिक आतंकवाद की घटनाएं बर्दी, जिससे दुनिया में यह धारणा बनी कि विश्व में आतंकवाद कट्टरवाद का परिणाम है। यह

हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया था? वह भारत ऐसा था जिसमें विभिन्न समुदायों ने मिलकर विदेशी शासन का मुकाबला किया। स्वतंत्रता का संघर्ष किसी एक जाति, धर्म या भाषा का संघर्ष नहीं था। वह पूरे भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन था। आज आवश्यकता इस बात की है कि वंदेमातरम् को विवाद का विषय बनाने के बजाय इतिहास और राष्ट्रीय चेतना के सम्मान के रूप में देखा जाए। जहां सम्मान आवश्यक है, वहां सम्मान हो; जहां संवैधानिक स्वतंत्रता का प्रश्न है, वहां संविधान सर्वोपरि हो; और जहां राजनीतिक मतभेद हों, वहां लोकतांत्रिक संवाद हो।

वंदेमातरम का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब उसके नाम पर समाज में दूरी नहीं, बल्कि देश के प्रति साझा जिम्मेदारी की भावना मजबूत हो। राजनीति को राष्ट्रभावना से प्रेरणा लेनी चाहिए, राष्ट्रभावना को राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए। भारत की शक्ति उसकी विविधता में है और उसकी लोकतांत्रिक परंपरा का मूल संदेश भी यही है कि असहमति के बावजूद देश सबसे ऊपर रहे। इसलिए समय आ गया है कि वंदेमातरम को लेकर होने वाली बहस नारों की राजनीति से ऊपर उठे। इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ा जाए, राष्ट्रीय प्रतीकों को सम्मान दिया जाए और लोकतांत्रिक अधिकारों को भी उतनी ही गंभीरता से समझा जाए। आखिरकार राष्ट्र केवल गीतों और नारों से नहीं बनता—राष्ट्र नागरिकों के विश्वास, संविधान की मर्यादा, सामाजिक सद्भाव और करोड़ों लोगों के ईमानदार योगदान से बनता है। वंदेमातरम् पर बहस हो तो भारत को जोड़ने के लिए हो, बांटने के लिए नहीं। यही उस गीत की ऐतिहासिक भावना के प्रति सच्चा सम्मान होगा।

लिए द्वार खोले। पर, उन्हें अपनी सेना के बहुमत का समर्थन नहीं मिला। उनके खिलाफ कम से कम 20 बार सशस्त्र विद्रोह या तख्तापलट के प्रयास हुए।

वे क्रूर तानाशाह के रूप में उभरे और उनके आलोचक फौजी अफसर या तो रहस्यमय ढंग से गायब हो गए अथवा मार डाले गए। यह आंकड़ा हैरान करता है कि उनके कार्यकाल के दरम्यान 1977 में 1143 लोगों को तख्तापलट की साजिश के आरोप में जेलों में फांसी दे दी गई थी। यही नहीं, जो फौजी अफसर शेख मुजीबुर्रहमान और उनके परिवार की हत्या में शामिल थे, वे जनरल जियाउर्रहमान की आंखों के तारे बन गए। उन्हें पदोन्नति दी गई अथवा अन्य देशों में भेज दिया गया। भारत के खिलाफ नफरत का जहर उगलने का काम इसी दौर में हुआ। हालांकि जियाउर्रहमान के विरुद्ध 21 वीं तख्तापलट साजिश कामयाब रही और उनका हथ्र भी वही हुआ, जो शेख मुजीब का हुआ था।

चटगांव में उनके आठ सुरक्षाकर्मियों के साथ उनकी हत्या कर दी गई। बाद में उनकी पार्टी बांग्ला नेशनलिस्ट पार्टी की बागडोर जिया की विधवा खालिदा जिया ने संभाली और तीन बार प्रधानमंत्री रहीं। जब शेख मुजीब की हत्या हुई तो बेटी शेख हसीना वाजेद जमीन में थीं। वहां से वे भारत आईं। भारत से जाकर बांग्लादेश में चुनाव लड़ा और अपनी पार्टी अवामी लीग को जीत दिलाई।

वे तीन बार देश की मुखिया बनीं। जाहिर था कि उन्हें प्रतिद्वंद्वी बीएनपी से प्रतिशोध लेना ही था। बीएनपी की मुखिया खालिदा जिया तमाम आरोपों में जेल में डाली गई। उनके बेटे और मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक रहमान तो अवामी लीग की एक रैली पर हमले में दोषी पाए गए। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हमले में अवामी लीग के 24 से अधिक शिखर नेता मारे गए थे। राष्ट्रपति की पत्नी और महिला अवामी लीग की अध्यक्ष श्रीमती रहमान भी मारी गई थीं। इस नरसंहार में एक बार फिर बीएनपी की भूमिका पाई गई थी।

‘दिमागी नक्सली’: क्या सच इतना कड़वा होता है?

नैरेटिव कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति को नुकसान पहुंचाने लगा। पाकिस्तान ने भी मुंबई 26/11 हमले में कसाब के हाथ में कलावा और जाली पहचान पत्र से हिन्दू आतंकवाद पर मोहर लगाने की नाकाम कोशिश की थी। पर कसाब के जिंदा पकड़े जाने से सच सामने आ गया।

2014 में भाजपा सरकार बनने के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र से काम शुरू हुआ। हजारों साल की गुलामी के प्रतीकों को हटाकर देश की मूल संस्कृति और मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास हुआ। देश के बहुपक्षों, वीरों और शहीदों का गौरवमयी इतिहास देश के नौजवानों के सामने लाया जाने लगा। इसे रोकने के लिए भगवाकरण शब्द गढ़ा गया, ताकि युवाओं को उनके आत्मबोध से दूर रखा जा सके।

दुनिया में अगर कहीं अभिव्यक्ति की आजादी है तो वह भारत है। एमरजेंसी में भी मीडिया ने हाथ से, ट्रैक्टर से, साइक्लोटाइल से सच जनता तक पहुंचाया। सच लिखने की कीमत शहादत के रूप में दी। ‘पंजाब केसरी’ इसका जवाब देना बड़ा उदाहरण है। जब यही मीडिया प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को प्रमुखता से दिखाने लगा तो विपक्ष ने इसे ‘गोदी मीडिया’ कह कर बदनाम किया। यह देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने की साजिश थी।

चौकीदार चोर, कातिल, मौत का सौदागर, सनातन एक कैसर, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हर घर से अफजल निकलेगा जैसे नारे और विद्यार्थी आंदोलनों में बलिच्यो से लगवाए गए अभद्र नारे-इन सबने हर देशभक्त और हर हिंदू के मन को आहत किया है। यही दिमागी नक्सलवाद है। जो लोग बिना बंदूक के देश के दिमाग में जहर पोतते हैं, उन्हीं के लिए प्रधानमंत्री ने यह शब्द इस्तेमाल किया। जय हिन्द जय भारत।

रुद्राक्ष का आध्यात्मिक और औषधीय महत्व

हिंदू धर्म में सदियों से पूजा-पाठ, यज्ञ, हवन जैसे शुभ कार्यों में रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता है। रुद्राक्ष के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। अब तो वैज्ञानिक अनुसंधानों के माध्यम से पूरी दुनिया में रुद्राक्ष की गुणवत्ता साबित हो चुकी है। इसके अद्भुत औषधीय गुण प्रयोगशाला में जांच के बाद सही साबित हुए हैं। इसे धारण करने से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है।

उत्पत्ति की कथा
वस्तुतः रुद्राक्ष शब्द का संधि विच्छेद है- रुद्र+अक्षि। अर्थात भगवान शिव का नेत्र। इसकी उत्पत्ति और नामकरण के पीछे यह कथा प्रचलित है कि त्रिपुरासुर का वध करते समय रुद्रावतार धारण किए भगवान शंकर की आंखों से बहने वाला जल रुद्राक्ष के रूप में पृथ्वी पर साकार हुआ। इसकी उत्पत्ति के संबंध में यह भी कहा जाता है कि जब हिमालय की पुत्री सती ने स्वयं को हवन कुंड में समाहित कर दिया था तो भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण कर लिया था और सती का शव कंधे पर उठा कर ब्रह्मांड का विनाश करने के लिए तांडव नृत्य करने लगे।

शिव जी को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे सती के शरीर के कई टुकड़े हो गए। टुकड़े जहां-जहां हिस्सों में गिरे, वहां-वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। अंत में भगवान शिव के शरीर पर सिर्फ सती के शरीर का भस्म रह गया। जिसे देखकर वह रो पड़े। इस तरह भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई।

स्वास्थ्यवर्धक औषधि
रुद्राक्ष एक वनस्पति है। इसके पेड़ पर बेर जैसे फल लगते हैं। ये पेड़ हिमालय की तराई में पाए जाते हैं। रुद्राक्ष के प्रभाव से आसपास का संपूर्ण वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसे रातभर भिगोकर रखने के बाद और प्रातःकाल नियमित रूप से खाली पेट इसका पानी पीना हृदय रोगियों के लिए बहुतलाभदायक साबित होता है। मान्यता के अनुसार, 1 से लेकर 35 मुंह तक के रुद्राक्ष उपलब्ध है। विविध कार्यसिद्धि के लिए विभिन्न रुद्राक्ष उपयोग में लाए जाते हैं। लेकिन गौरी-शंकर नामक संयुक्त रुद्राक्ष, पैंतीस मुखी एवं एकमुखी रुद्राक्ष बहुत कम प्राप्त होते हैं। पुराना रुद्राक्ष अधिक प्रभावशाली



होता है।

रुद्राक्ष के विभिन्न प्रकार
रुद्राक्ष की अलग-अलग किस्मों के लाभ भी अलग होते हैं। यहां प्रस्तुत है रुद्राक्ष के प्रमुख प्रकार और उनके फायदे:
● एकमुखी रुद्राक्ष: यह आंख, नाक, कान और गले की बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है।

- द्विमुखी रुद्राक्ष: यह मस्तिष्क की शांति, धैर्य और सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि में सहायक होता है। साथ ही इसे धारण करने से पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं भी काफी हद तक दूर हो जाती हैं।
- पंचमुखी रुद्राक्ष: यह पंच ब्रह्म तत्व का प्रतीक है। यह युवाओं के जीवन को सही दिशा देता है। इससे धन और मान-सम्मान में वृद्धि होती है और यह उच्च रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है।
- ससमुखी रुद्राक्ष: यह भगवान कार्तिकेय का प्रतीक

माना जाता है तथा इसे धारण करने से आंखों की दृष्टि में वृद्धि होती है।

आमतौर पर चतुर्मुखी रुद्राक्ष शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए, पंचमुखी रुद्राक्ष नित्य जप के लिए, षड्मुखी रुद्राक्ष पुत्र प्राप्ति के लिए, चतुर्दश एवं पंचदशमुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तथा इक्कीस मुखी रुद्राक्ष ज्ञान प्राप्ति के लिए धारण करने की प्रथा है।

कैसे धारण करे रुद्राक्ष
रुद्राक्ष स्वभाव से ही प्रभावी होता है, लेकिन यदि उसे विशेष पद्धति से सिद्ध किया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक हो जाता है। अगर जप के लिए रुद्राक्ष की माला सिद्ध करनी हो तो सबसे पहले उसे पंचगव्य में डुबोएं, फिर साफ पानी से धो लें। हर मनके पर 'ईशानः सर्वभूतानां' मंत्र का 10 बार जप करें।

यदि रुद्राक्ष के सिर्फ एक मनके को सिद्ध करना हो तो पहले उसे पंचगव्य से स्नान कराएं और उस पर गंगाजल का छिड़काव करें। उसके बाद षोडशोपचार से पूजा करके उसे चांदी के डिब्बे में रखें। हाथों में कुश लेकर उसका स्पर्श रुद्राक्ष से करके इच्छित इष्टमंत्र का जप करें।

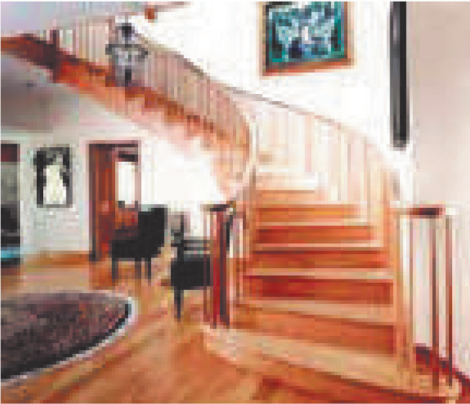
विविध रुद्राक्ष विभिन्न कार्यों के लिए काम में लाए जाते हैं। इसलिए उनके मंत्र एवं सूक्त भी अलग-अलग हैं। श्रीसूक्त, विष्णुसूक्त, पवमान रुद्र, मन्युसूक्त, चतुर्दश प्रणवात्मक महामृत्युंजय, शांतिसूक्त, रुद्रसूक्त तथा सौरसूक्त आदि का उपयोग कार्यानुसार रुद्राक्ष सिद्धि के लिए किया जाता है। रुद्राक्ष सिद्ध करना सहज है, लेकिन उसकी सिद्धि बनाए रखना मुश्किल है।

असत्य वचन और बुरे व्यवहार आदि कारणों से रुद्राक्ष की सिद्धि कम हो जाती है। अतः इसे धारण करने वाले व्यक्ति को सदाचार का पालन करना चाहिए।

गले में 108 या 32 रुद्राक्षों की माला पहनने की प्रथा है। हाथों में भी 27, 54 या 108 रुद्राक्षों की माला पहननी चाहिए। भगवान शिव का पूजन करते समय रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। शरीर से रुद्राक्ष का स्पर्श होना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है।

घर की पूर्व दिशा में बनवाएं सीढ़ियां

वास्तु



यदि मकान बहुमंजिला है तो उसमें सीढ़ियां अवश्य होंगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार, घर का प्रत्येक हिस्सा महत्वपूर्ण होता है और घर के सदस्यों पर उनका विशेष प्रभाव भी होता है। अतः वास्तु के अंतर्गत सीढ़ियों के संबंध में कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

- सीढ़ियों का उतार-चढ़ाव ढलान के अनुसार ही होना चाहिए। सीढ़ियों पर पूर्व से पश्चिम की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ चढ़ाई हो सकती हैं।
- यदि सीढ़ियां बीच में घुमावदार हों तो यह घुमाव चढ़ते समय क्लॉकवाइज यानी बाएं से दाएं होनी चाहिए। चूँकि पृथ्वी भी इसी दिशा में घूमती है और चढ़ते समय एनर्जी भी अधिक खर्च होती है, इसलिए क्लॉकवाइज घूमते हुए ही चढ़ना चाहिए ताकि अतिरिक्त ऊर्जा न लगानी पड़े।
- चूँकि उतरते समय कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए एंटी-क्लॉकवाइज घूमते हुए भी उतरा जा सकता है।
- बड़े भवनों में नीचे से दो तरफ से सीढ़ियां चढ़ाई जाती हैं और घुमाव के स्थान पर मिलाते हुए ऊपर कर दी जाती है अथवा नीचे से एक सीढ़ी चढ़ाते हुए घुमाव के स्थान पर दो भागों में दो तरफ चढ़ा दी जाती है, इससे चढ़ते व उतरते समय क्लॉकवाइज घूमा जा सकता है।
- यदि सीढ़ियां बिल्कुल सीधी हैं और बीच में कोई

घुमाव नहीं है तब भी छत पर प्रवेश करते समय घड़ी की सुइयों की दिशा में ही दरवाजा होना चाहिए ताकि छत के कमरे में प्रवेश करते समय क्लॉकवाइज घूमना पड़े। एंटी-क्लॉकवाइज घुमाव वाला दरवाजा न रखें। यदि सीढ़ियां सीधे ही छत के कमरे में प्रवेश करती हों तब किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

- भवन के मध्य भाग में कोई पिलर अथवा सीढ़ियां नहीं बनवाई जानी चाहिए।

- वास्तु सम्मत सीढ़ियां भवन के पूर्व या दक्षिण दिशा में बनवाई जानी चाहिए।

जानें, किस तरह पानी की स्थिति दिलाती है घर में परेशानी से निजात

पानी का बर्तन रसोई के उत्तर-पूर्व या पूर्व में भरकर रखें। घर में पानी सही स्थान, सही दिशा में रखने से परिवार का स्वास्थ्य अनुकूल व सुख-समृद्धि में वृद्धि होती।

पानी का बर्तन रसोई के उत्तर-पूर्व या पूर्व में भरकर रखें। घर में पानी सही स्थान पर और सही दिशा में रखने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अनुकूल रहता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।

पानी का स्थान ईशान कोण है अतः पानी का भण्डारण अथवा भूमिगत टैंक या बोरिंग पूर्व, उत्तर या पूर्वोत्तर दिशा में होनी चाहिए। पानी को ऊपर की टंकी में भेजने वाला पंप भी इसी दिशा में होना चाहिए।

दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पश्चिम अथवा दक्षिण-पश्चिम कोण में कुआं अथवा ट्यूबवेल नहीं होना चाहिए। इसके लिए उत्तर-पूर्व कोण का स्थान उपयुक्त होता है। इससे वास्तु का संतुलन बना रहता है।

अन्य दिशा में कुआं या ट्यूबवेल हो, तो उसे भरवा दें और यदि भरवाना संभव न हो, तो उसका उपयोग न करें। नहाने का कमरा पूर्व दिशा में शुभ होता है।

ध्यान रखें, घर के किसी नल से पानी नहीं रिसना चाहिए अन्यथा भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। ओवर हेड टैंक उत्तर और वायव्य कोण के बीच होना चाहिए। टैंक का ऊपरी भाग गोल होना चाहिए।

खुशहाली के लिए लगाएं रत्नों का पौधा

रत्नों का पौधा सुनने में भी भले ही काल्पनिक लगे किन्तु वास्तविकता यही है कि चीनी पद्धति में इस पौधे का अधिक महत्व है। यह पौधा तरह-तरह के रत्नों और स्फटिकों का बना होता है। इसमें कई वैरायटीज होती हैं।

नवबर पेड़ नवग्रहों की शांति, सुख तथा पारिवारिक शांति के लिए उपयोग किया जाता है। एमेथिस्ट का पेड़, दिमाग का संतुलन बनाए रखता है। रंग-बिरंगे रत्नों से सजे इस पौधे को यदि घर के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में रखा जाए तो निश्चित रूप से जीविका चलाने वाले व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसे घर में दक्षिण-पूर्व दिशा में भी रखा जा सकता है। इसे व्यवसायिक स्थल पर रखने से सम्पदा मिलती है। इसे बैठक में भी रखा जा सकता है। इसका एक ओर महत्वपूर्ण कार्य नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना भी है। चीनी संस्कृति और फेंगशुई में ड्रैगन को बहुत सम्मान दिया जाता है और इसे शुद्ध मानते हैं।

कई पीढ़ियों से ड्रैगन शक्ति, अच्छे भाग्य और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ड्रैगन एक कीमती कास्मिक ची बनाता है, जिसे शेंग ची भी कहते हैं, जिससे घर और कार्यस्थल पर भाग्य साथ देता है। डबल ड्रैगन को यूं तो किसी भी दिशा में रखा जा सकता है, लेकिन पूर्व दिशा में रखना सबसे ज्यादा कारगर माना गया है।

यह ड्रैगन लकड़ी, सेरेमिक व धातु में उपलब्ध है। दो ड्रैगन का जोड़ा समृद्धि का प्रतीक है। इनके पैर के पंजों में ज्यादा मोती सबसे ज्यादा ऊर्जा संजोये है। फेंगशुई में ड्रैगन को चार दिव्य प्राणियों में गिना जाता है। ड्रैगन येंग यानी पुरुषत्व, हिम्मत और बहादुरी का प्रतीक है। लकड़ी के ड्रैगन को दक्षिण- पूर्व



या पूर्व में, सेरेमिक, क्रिस्टल के ड्रैगन को दक्षिण- पूर्व, उत्तर-पूर्व वया उत्तर पश्चिम में रखें।

छात्र इसे अपनी पढ़ाई की टेबल पर रखें। घर की उत्तर-पश्चिम दिशा में इसे रखने से अच्छे सलाहकार, दोस्त व बढिया नेतृत्व करने वाले साथी मिलेंगे।

नहीं चाहते किसी से विवाद, तो आजमाइए यह लाजवाब उपाय

जैन धर्म ही नहीं, बल्कि संसार का हर धर्म क्षमा के महत्व को मानता है। माफी मांगना और माफ करना दोनों ही मनुष्य के व्यक्तित्व को पूर्ण करने वाले तत्व हैं।

क्षमा का अर्थ है, 'किसी के द्वारा की गई गलती को स्वेच्छे से समाप्त कर देना।' जैन धर्म में क्षमा 'क्षमावाणी' पर्व रूप में मनाई जाती है। इस पर्व को जैन धर्म के अनुयायी दशलक्षण महापर्व के रूप में मनाते हैं। दस दिन, दस सिद्धांतों को मानते हुए राजाओं का बल दंड है और गुणवानों का क्षमा है।' ठीक इसी तरह जैन संत विद्यासागर जी महाराज

कहते हैं, 'अपने मन में क्रोध को पैदा न होने देना और अगर हो भी जाए तो अपने विवेक से, नम्रता से उसे विफल कर देना चाहिए। स्वयं से जाने-अनजाने में हुई गलतियों के लिए खुद को क्षमा करना और दूसरे के प्रति भी इसी भाव को रखना क्षमा पर्व का महत्व है।

अन्य धर्मों में क्षमा जैन धर्म ही नहीं, बल्कि संसार का हर धर्म क्षमा के महत्व को मानता है। क्षमा मांगने से अहंकार खत्म हो जाता है। महाभारत में क्षमा के बारे में उल्लेख मिलता है, 'दुष्टों का बल हिंसा है, दसवें दिन क्षमावाणी का पर्व मनाया जाता है।' ठीक इसी तरह श्रीमद्भागवद् में उल्लेखित है, 'वही साधुता



क्षमा का मनोविज्ञान मनोविज्ञानी भी क्षमा के महत्व को मानते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार, 'क्षमा का मनुष्य के व्यक्तित्व में बहुत महत्व होता है। यदि कोई आदमी माफी मांगने पर भी किसी को माफन करे तो उसके व्यक्तित्व में भी 'अहम' संबंधी विकार होता है। यानी माफी मांगना और माफ करना दोनों ही मनुष्य के व्यक्तित्व को पूर्ण करने वाले तत्व हैं।

लंका में प्रवेश और लंकिनी पर प्रहार



सौ योजन चौड़े विशाल समुद्र को पार कर हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए शीघ्र ही लंका नगरी के निकट जा पहुंचे। वहां का दृश्य बड़ा ही सुहावना था। चारों ओर तरह-तरह के सुंदर वृक्ष लगे हुए थे। सुंदर-सुंदर फूल खिले हुए थे। भांति-भांति के पक्षी आनंद में चहक रहे थे।

शीतल, मंद, सुगंधित हवा बह रही थी। बड़ा ही मनमोहक दृश्य था लेकिन श्री हनुमान जी का मन इस समय प्राकृतिक छटा में बिना डूबे लंका में प्रवेश की योजना बनाने में खोया हुआ था। महावीर हनुमान जी ने सोचा कि माता सीता जी को रावण ने जिस स्थान पर छुपा कर रखा है उसका पता तो मुझे लगाना ही है और साथ ही मुझे यहां के बारे में अन्य आवश्यक बातों भी जान लेनी चाहिए। मुझे यहां पूरी सेना के ठहरने लायक स्थान, जल-फल की सुविधा आदि का पता भी करना चाहिए। रावण का दुर्ग (किला) दूर से ही देखने पर अत्यंत दुर्गम मालूम पड़ता है।

अतः युद्ध के विचार से इसकी एक-एक बात का पता लगा लेना भी आवश्यक है परन्तु अपने असली रूप में और वह भी दिन के उजाले में इस नगरी में प्रवेश करना तो बहुत बड़ी भूल होगी। इसीलिए रात्रि के समय सबके सो जाने पर सूक्ष्म वेश धारण करके ही मेरा इस नगरी में प्रवेश करना उचित होगा। रात हो जाने पर मच्छर के समान अत्यंत छोटा रूप बन कर तथा मन ही मन प्रभु श्री राम चंद्र जी का स्मरण करते हुए हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। चारों ओर भयानक व विकराल राक्षस-राक्षसियों का पहरा था।

वह नगरी बहुत अच्छी तरह से बसाई गई थी। सड़कें-चौराहे सब बहुत ही सुंदर थे। उसके चारों ओर समुद्र था। पूरी नगरी सोने की बनी हुई थी। स्थान-स्थान पर सुंदर बगीचे और जलाशय बने हुए थे। हनुमान जी अत्यंत सावधानी के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि लंका की रक्षा करने वाली लंकिनी राक्षसी ने उन्हें पहचान लिया। उसने आगे बढ़ कर हनुमान जी को डराते हुए कहा, “अरे! तू कौन है? जो चोर की तरह छिप कर लंका में प्रवेश कर रहा है। क्या तुझे यह पता नहीं है कि लंका में घुसने वाले चोर ही मेरे आहार हैं? इससे पहले कि मैं तुझे खा जाऊं-तू अपना सारा रहस्य बता दे कि यहां क्यों आया है?”

हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं इससे किसी प्रकार का विवाद करता हूं तो शोर सुनकर बहुत से राक्षस यहां इकट्ठे हो जाएंगे। अतः मुझे इसे बेहोश करके आगे बढ़ जाना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने बाएं हाथ की मुष्टिका (मुट्ठी) से उस पर प्रहार किया। उस प्रहार से वह मुंह से खून फैंकती हुई बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी किंतु शीघ्र ही वह पुनः उठकर खड़ी हो गई। उसने कहा, “वानर वीर! अब मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम भगवान श्री राम चंद्र जी के दूत हनुमान हो। मुझसे बहुत पहले ब्रह्मा जी ने कहा था, ‘त्रेतायुग में हनुमान नामक एक वानर लंका में सीता जी की खोज करता हुआ आएगा। तू उसकी मार से बेहोश हो जाएगा। जब ऐसा हो तब समझना कि शीघ्र ही सारे राक्षसों के साथ रावण का संहार होने वाला है। वीर रामदूत हनुमान! अब तुम निर्भय होकर लंका में प्रवेश करो। मेरा परम सौभाग्य है कि ब्रह्मा जी की कृपा से मुझे परम पवित्र श्री रामदूत के दर्शन हुए।’”



कश्मीर पर मिला अमेरिका का साथ, चिढ़ा पाकिस्तान

श्रीनगर। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर का दौरा किया. कश्मीर पहुंचने के बाद गोर ने साफ शब्दों में कहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत का एक बेहद अहम हिस्सा है. भारत की लंबे समय से चली आ रही स्थिति पर अमेरिकी दूत का यह बयान काफी मजबूत समर्थन माना जा रहा है. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर द्वारा जम्मू कश्मीर पर की गई टिप्पणी से पाकिस्तान जल-भूत गया है. पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को जम्मू-कश्मीर यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया.गौरतलब है, आर्टिकल 370 हटने और हालिया सुरक्षा घटनाओं के बाद किसी अमेरिकी राजदूत का यह पहला कश्मीर दौरा है. श्रीनगर पहुंचने के बाद अमेरिकी दूत सर्जियो गोर ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की. इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई।

वंदे मातरम के शुरुआती दो पैरा ही गाएगी कांग्रेस

नईदिल्ली। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और सत्ता पक्ष के बीच विवाद जारी है. इस मुद्दे को लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्यसमिति में चर्चा हुई. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में कई नेताओं ने 1937 के पार्टी के स्टैंड को दोहराया. इसका मतलब ये है कि कांग्रेस 1937 के वर्जन (पहले दो पैरा) को ही अपने कार्यक्रमों में गाएगी. बैठक के बाद हुई पत्रकार वार्ता में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, वंदे मातरम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था. जब उस प्रस्ताव को पारित किया गया तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य नरेंद्र देव और अन्य नेता मौजूद थे.उन्होंने आगे कहा, रबींद्रनाथ टैगोर की सलाह से ही वो प्रस्ताव पारित किया गया था और आज उस पर चर्चा हुई।

तीन महीने में नहीं सीखी मराठी तो लाइसेंस कैसिल

मुंबई। महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्षा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि जो रिक्षा और टैक्सी चालक मराठी सीखने से इनकार करेंगे और इसे लेकर मनमानी करेंगे, उनके खिलाफ कानून के दायरे में कार्रवाई की जाएगी. एक महीने का नोटिस और इसके बाद तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित किए जाने के बावजूद मराठी नहीं सीखने पर चालक का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि महाराष्ट्र में पिछले 105 दिनों से टैक्सी और रिक्षा चालकों को मराठी सिखाने का अभियान चलाया जा रहा है. अब तक करीब 1 लाख 65 हजार ऑटो-रिक्षा और टैक्सी चालक मराठी सीख चुके हैं और उन्हें इसके प्रमाणपत्र भी दिए गए हैं. सरनाईक ने कहा कि महाराष्ट्र के साथ-साथ दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को भी यहां रोजगार मिलना चाहिए।

रामदेव-कंगना में खटपट

नई दिल्ली। बीजेपी की सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने योग गुरु बाबा रामदेव पर पलटवार किया है. कंगना ने हाल ही में देश के लद्दु " को "गटर जेनरेशन%" कहा था, जिस पर रामदेव ने कड़ी आपर्ति जताई थी और एक्ट्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उनकी खुद की लाइफ पर सवाल खड़े कर दिए थे. बाबा रामदेव के इस कमेंट पर अब कंगना ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है. कंगना ने योग गुरु को नसीहत देते हुए साफ कहा कि वह उनकी जवानी या निजी जिंदगी के बारे में सपने देखना छोड़ दें और उन्हें चरित्र का पाठ न पढ़ाएं. कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा-चौड़ा नोट शेयर कर बाबा रामदेव पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने लिखा, %बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिन में सपने मत देखो. कोई केवल अफवाहों और गॉसिप के आधार पर अंदाजा ही लगा सकता है.% कंगना ने पतंजलि से जुड़े विवादों और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का जिक्र करते हुए आगे कहा कि कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूटे या फ़ॉड मेडिकल दावों के लिए फटकार नहीं पड़ी है।

गंगा के पानी पर बांग्लादेश की नजर

नई दिल्ली। दिसंबर 2026 में 1996 की गंगा जल संधि की मियाद पूरी हो रही है. बांग्लादेश ने नई संधि में तीन सीजन के लिए %गारंटी क्लॉज% जोड़ने की मांग की है और फरक्का बैराज पर सवाल उठाते हुए जरूरत पड़ने पर अंतरराष्ट्रीय मंचों का रुख करने की चेतावनी दी है.भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा के पानी का मुद्दा एक बार फिर दोनों देशों के रिश्तों के केंद्र में आ गया है. 1996 में हुई गंगा जल संधि की मियाद दिसंबर 2026 में खत्म होने वाली है. इस समझौते के रिन्युअल से पहले बांग्लादेश ने नई संधि को लेकर अपना रुख सख्त कर दिया है. बांग्लादेश ने कहा है कि वह नई संधि में एक ऐसे %गारंटी क्लॉज% की मांग करेगा. गारंटी क्लॉज का अर्थ है कि सूखे के मौसम में भी बांग्लादेश को पानी की सप्लाई होती रहे. इस मुद्दे पर जरूरत पड़ने पर ढाका अंतरााष्ट्रीय मंचों का रुख करने के लिए भी तैयार है. बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने मंगलवार को ढाका में 'गंगा जल संधि रिनैगोसिएशन के मुद्दे' विषय पर आयोजित एक सेमिनार में यह बात कही. यह कार्यक्रम बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड इंटरनेशनल अफेयर्स ने आयोजित किया था।

अमित शाह की बैठक में दिखा साउथ का पावर शो

एक मंच पर थलपति विजय, शिवकुमार और चंद्रबाबू नायडू

चेन्नई। तमिलनाडु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्रियों ने कई अहम मुद्दे उठाए। इनमें परिसीमन, दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा, नीट परीक्षा, कावेरी जल बंटवारा और ज्यादा वित्तीय स्वायत्तता जैसे मुद्दे शामिल थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दक्षिण की संसदीय ताकत को सुरक्षित रखने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव की मांग की, वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया के बाद इस क्षेत्र की राजनीतिक आवाज में किसी भी तरह की कमी को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों पर जोर दिया।

कर्नाटक ने मेकेदातु प्रोजेक्ट पर सहयोग मांगा, जबकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गोदावरी-कावेरी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के जरिए 500 टीएमसी से ज्यादा पानी को दूसरी तरफ मोड़ने का प्रस्ताव रखा। केरल ने भी पेशकश की कि अगर तमिलनाडु प्रस्तावित नए मुल्लापेरियार बांध वाले प्रोजेक्ट के लिए सहमत हो जाता है, तो उसे वहां से पानी मिलना सुनिश्चित किया जाएगा; साथ ही, केरल ने बंदरगाहों, रेल



कनेक्टिविटी, तटीय सुरक्षा और अंतर-राज्यीय सुरक्षा के मामलों में ज्यादा क्षेत्रीय सहयोग की भी मांग की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने कार्टिसिल के सामने परिसीमन और नीट से जुड़ी चिंताएं जोर-शोर से रखीं। उन्होंने तर्क दिया कि जिन राज्यों ने आबादी को स्थिर करने की नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया है, उन्हें इसके नतीजे के तौर पर अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं खोना चाहिए। विजय ने कहा कि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों के आवंटन पर लगी रोक खत्म होने वाली है। उन्होंने चिंता जताई कि आबादी के आधार पर परिसीमन से दक्षिणी राज्यों की सामूहिक संसदीय आवाज कमजोर हो सकती है। उन्होंने केंद्र से स्पष्ट

करने, मानव विकास और आर्थिक विकास में सबसे आगे रहे हैं। ये उपलब्धियां राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सफल कार्यान्वयन को दर्शाती हैं और इनके कारण हमारे प्रतिनिधित्व में कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा सार्वजनिक नीति के तहत राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने वाले राज्यों को अनजाने में ढंड़ित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने ऐसे सुरक्षा उपायों की भी मांग की जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि परिसीमन से दक्षिण के राजनीतिक प्रभाव पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। कावेरी नदी जल बंटवारे के मुद्दे और मेकेदातु बांध विवाद की पृष्ठभूमि में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में कर्नाटक के अपने समकक्ष शिवकुमार के साथ बातचीत की।

कानूनी आश्वासन मांगा कि आबादी को स्थिर करने में सफलता के कारण किसी भी राज्य के स ें स दी य प्रतिनिधित्व के प्रतिशत में कमी नहीं आएगी। विजय ने कहा दक्षिणी राज्य आबादी को स्थिर करने, मानव विकास और आर्थिक विकास में सबसे आगे रहे हैं। ये उपलब्धियां राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सफल कार्यान्वयन को दर्शाती हैं और इनके कारण हमारे प्रतिनिधित्व में कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा सार्वजनिक नीति के तहत राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने वाले राज्यों को अनजाने में ढंड़ित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने ऐसे सुरक्षा उपायों की भी मांग की जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि परिसीमन से दक्षिण के राजनीतिक प्रभाव पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। कावेरी नदी जल बंटवारे के मुद्दे और मेकेदातु बांध विवाद की पृष्ठभूमि में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में कर्नाटक के अपने समकक्ष शिवकुमार के साथ बातचीत की।



राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में वैचारिक लड़ाई सिर्फ पर्यावरण, राजनीति या स्वतंत्र मीडिया जैसे मुद्दों तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक, असली सवाल यह है कि क्या कोई समूह यह तय कर सकता है कि देश के हर व्यक्ति की सच्चाई वही जानता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों से जुड़े एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि इसका मतलब यह संदेश देना है कि मैं सब कुछ जानता हूं, आप कुछ नहीं जानते।

राहुल गांधी ने कहा कि जब छात्रों ने विरोध किया तो मोहन भागवत की ओर से भी छात्रों पर हमला नहीं करने की बात कही गई, लेकिन उनके अनुसार छात्रों पर लगातार हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि वे उनकी सच्चाई जानते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश के हर कारोबार का मालिक एक ही व्यक्ति हो तो बड़ी आबादी के लिए स्वराज संभव नहीं है। उन्होंने कहा अगर एक व्यक्ति इस देश के हर एक कारोबार का मालिक है तो भारतीय

लोगों की बड़ी आबादी के लिए स्वराज की कोई संभावना नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में कुछ लोगों के पास एयरपोर्ट, बंदरगाह और कंपनियां होनी चाहिए, जबकि दूसरे लोग ऐसे नौकरशाह होने चाहिए जो अपनी बात स्वतंत्र रूप से रख सकें और किसी कारोबारी के प्रभाव में आकर काम करने के लिए मजबूर न हों।

राहुल गांधी ने कहा कि गांधीजी का विजन कुछ बुनियादी व्यवस्थाओं के बिना पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने महंगी शिक्षा व्यवस्था और असमान परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह विजन ऐसी वित्तीय व्यवस्था के साथ भी संभव नहीं है, जिस पर दो-तीन लोगों का एकाधिकार हो। राहुल गांधी ने राजनीतिक व्यवस्था की पहुंच गांवों और पंचायतों तक होने की जरूरत बताई। उन्होंने पंचायती राज, विधायक और सांसदों का भी उल्लेख किया।

राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर समाज के अलग-अलग वर्गों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के मुस्लिम, ईसाई और सिख समुदायों को यह संदेश दिया गया कि उनका अस्तित्व नहीं है। उन्होंने आदिवासियों और दलितों को लेकर भी भाजपा और आरएसएस पर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों को उनकी जमीन और दलितों की जातिगत भेदभाव से जुड़े मुद्दों पर दबाव्या जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में इस स्थिति को बदलने की जरूरत है।

राहुल गांधी ने कहा कि देश में हर व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि वह भारत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि धर्म, समुदाय, उम्र या महिला-पुरुष के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक हर एक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी धर्म, समुदाय, उम्र या लिंग का हो, यह महसूस होना चाहिए कि मैं यहां का हूं।

पहले सीमाओं की अनदेखी हुई, अब शीर्ष प्राथमिकता : रिजजू

नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजजू ने गुरुवार को कहा कि देश की सीमा से सटे इलाके, जिनकी पहले अनदेखी की गई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शीर्ष प्राथमिकता बन गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सीमाई इलाकों में विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। किरेन रिजजू ने एएस पर अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों माजा, गालेमो और तकिंस के दौरे का एक वीडियो भी पोस्ट किया। वीडियो में बुनियादी ढांचे के काम के लिए मशीनें चलती दिखीं। केंद्रीय मंत्री ने सेना के जवानों और स्थानीय लोगों से बातचीत की। वीडियो में दुर्गम और ऊबड़-खाबड़ हिमालयी इलाका भी दिखा जो सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है।

एक्स पर पोस्ट करते हुए किरेन रिजजू ने लिखा, कुछ लोग सीमा को लेकर लापरवाही से टिप्पणी कर देते हैं। सीमाई क्षेत्र मुश्किल हैं, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार सीमा के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मैं अरुणाचल प्रदेश के माजा, गालेमो, तकिंस इलाकों में गया ताकि बुनियादी ढांचे के काम तेज किए जा सकें। पहले सीमाओं की अनदेखी हुई थी लेकिन अब यह शीर्ष प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब विपक्षी नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार चीनी चुसपैठ की जानकारी छिपा रही है। सीमा पर भारतीय क्षेत्र की ठीक से रक्षा नहीं कर रही है।इससे पहले बुधवार को आईएनएस से विशेष बातचीत में किरेन रिजजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस दावे को खारिज किया।

उन्होंने कहा, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर मुद्दे हैं। इन मुद्दों की जड़ को समझने की जरूरत है। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन की बहुत लंबी सीमा है जिसे औपचारिक रूप से तय नहीं किया गया है। वहां कोई सीमा स्तंभ नहीं हैं और जमीन पर सीमा रेखा साफ नहीं है। यह कोई नई बात नहीं है। जब लिब्वा एक अलग इकाई था, तब भी लिब्वात और भारत के बीच सीमा तय नहीं थी। उन्होंने कहा, लोगों के लिए अलग-अलग वीडियो शेयर करके भ्रम फैलाना गलत है। सीमा को लेकर वाकई एक मुद्दा है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ ग्रामीणों ने सीमा को लेकर चिंता जताई है। यह सही भी है, क्योंकि वहां सीमा तय नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस इलाके की दुर्गम जमीन के कारण पहले यहां स्थायी बसावट कम थी। इन इलाकों का इस्तेमाल पहले शिकार और चराई के लिए होता था, रहने के लिए नहीं। सीमा तय न होने के कारण भारत और चीन के बीच लंबे समय से तनाव रहा है।



स्टेल प्रमुख समाचार

भारतीय टीम के लिए नॉकआउट की तरह ही होगा दूसरा दौर

एम्स्टेलवीन। आखिरी फूल मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराकर दूसरे दौर पहुंची भारतीय पुरुष हॉकी टीम की राह अब आसान नहीं होगी और पहले ही मैच में शुरुवार को उसका सामना पेरिस ओलंपिक स्पर्ध पदक विजेता नीदरलैंड हो सकता है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। मैच शाम छह बजे से (भारतीय समयानुसार रात 9.30 से) होगा। पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 और 4-1 से बढ़त बनाने के बाद जिस तरह से भारत ने पकड़ ढीली की, वह नीदरलैंड जैसे टीमों के खिलाफ भारी पड़ सकती है। भारत ने फूल डी में वेल्स को 3 -1 से और पाकिस्तान को 5-3 से हराया जबकि इंग्लैंड से 2-4 से हार गई।

नए प्रारूप के तहत फूल डी की दोनों शीर्ष टीमें और फूल ए की दो शीर्ष टीमें से फूल ई बना है जिसमें से पहली दो टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। वहीं फूल बी और सी की शीर्ष दो टीमें फूल एफ में एक दूसरे से खेलेंगी और पहले दो स्थान की टीमें अंतिम चार में पहुंचेंगी। पहले चरण में इंग्लैंड से हारने के कारण भारतीय टीम दूसरे दौर में उसके खिलाफ नहीं खेलेगी जबकि इंग्लैंड पहले दौर के तीन अंक लेकर इस दौर में पहुंची है। इसके मायने हैं कि भारत को बाकी दोनों टीमों से जीतना ही होगा।

फूल ए में दुनिया की दूसरे नंबर की टीम नीदरलैंड फिलहाल शीर्ष पर है जिसे बृहस्पतिवार को जापान से आखिरी ग्रुप मैच खेलना है। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए नीदरलैंड का जीतना लगभग तय है क्योंकि जापान पहले दोनों मैच हारकर दौड़ से पहले ही बाहर हो चुका है। वहीं दूसरे मैच में विश्व रैंकिंग में आठवें स्थान पर काबिज अर्जेंटीना का सामना 11वीं रैंकिंग वाली न्यूजीलैंड से होगा जिसमें दूसरे दौर में जाने वाली एक और टीम का निर्धारण होगा।

आर्थिक/वणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

सैंसेक्स 628 अंक चढ़ा निफ्टी 24231 पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजारों में 7 दिनों से जारी कमजोरी पर ब्रेक लग गया है। बेंचमार्क इंडेक्स गुरुवार (20 अगस्त) को बढ़त के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 628 अंक उछलकर 77537 पर बंद



हुआ। एनएसई निफ्टी 50 भी 153 अंक चढ़कर 24231 पर बंद हुआ। बाजार में लौटी टेजी से निवेशकों को करीब 2.6 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा तेजी एंटरनल, श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में दर्ज की गई, जो 2-2.5 फीसदी तक उछले। कोटक बैंक, आईटीसी, बजाज फाइनेंस समेत एक्सिस बैंक के शेयर भी टॉप गेनर में शामिल रहे। वहीं, टाटा कंज्युमर्स का शेयर 1.1 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लुजर रहा। चौतरफा खरीदारी में रियल्टी, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक सेक्टर टॉप गेनर रहे।

त्योहारों से पहले चीनी की कीमतों पर लगाम की तैयारी

नईदिल्ली। देश में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची चीनी की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने स्टॉक रखने के नियम और सख्त कर दिए हैं। नए आदेश के मुताबिक, हर महीने 10 टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करने वाला कोई भी डीलर 15 दिन से अधिक का स्टॉक नहीं रख सकेगा। सरकार का मकसद बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और बढ़ती कीमतों को काबू में रखना है। नोटिफिकेशन के अनुसार, यह आदेश 1 सितंबर से लागू होगा और 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने पिछले महीने चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्टॉक रखने पर पाबंदी लगाई थी। उस समय डीलरों को अधिकतम 30 दिन तक चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति थी। अब इसे 15 दिन कर दिया गया है। सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं।

एचडीएफसी बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीद सकेगी एलआईसी

नईदिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.99 फीसदी तक करने की मंजूरी दे दी है। एचडीएफसी बैंक ने शेयर बाजार की दी जानकारी में यह बात कही है। बैंक के मुताबिक, आरबीआई ने 19 अगस्त 2026 के पत्र के जरिये एलआईसी को एचडीएफसी बैंक की पेड-अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट्स में कुल हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.99 फीसदी तक करने की अनुमति दी है। इसका असर गुरुवार को एचडीएफसी बैंक के शेयरों पर दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में शेयर 1 फीसदी तक उछल गया। एचडीएफसी बैंक ने बताया कि 14 अगस्त 2026 तक उपलब्ध ताजा बेनिफिशियल होल्डिंग के मुताबिक एलआईसी के पास बैंक की कुल शेयर कैपिटल में 4.11 फीसदी हिस्सेदारी थी।

जापान का जुलाई में निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

नईदिल्ली। जापान का जुलाई में निर्यात और आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। हालांकि बढ़ती ऊर्जा लागत एवं कमजोर येन से देश का व्यापार घाटा लगातार तीसरे महीने बढ़ा। सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। वित्त मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार को जारी प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, जापान का व्यापार घाटा पिछले महीने 634.5 अरब येन (चार अरब अमेरिकी डॉलर) रहा। देश में लगातार तीसरे महीने व्यापार घाटा दर्ज किया गया। मौसमी रूप से समायोजित आयात जुलाई में सालाना आधार पर 27.8 प्रतिशत बढ़कर 12.15 लाख करोड़ येन (77 अरब डॉलर) हो गया। पश्चिम एशिया तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। जापान अपनी जरूरत का लगभग पूरा तेल आयात करता है।

आर्थिक समृद्धि के लिए सही नीतियों से ज्यादा जरूरी है सक्षम नेतृत्व

देवाशिष बस

आर्थिक समृद्धि का रास्ता क्या है? इसके आदर्श जवाब में विभिन्न मॉडल, नीतियां और योजनाएं आदि शामिल होती हैं। परंतु यह निष्कर्ष निकालना कि सही नीतियां और मॉडल खुदबखुद समृद्धि ले आएंगे, ऐसा ही है जैसे 'यह मानना कि अगर अण्डों, कीर्ति और आटे को रात भर मिलाकर छोड़ दिया जाए तो वह खुद केक में बदल जाएगा।' सिंगापुर की राजनीति विज्ञानी और 'हाउ चाइना एक्स्पेंड टॉर्पेंट्री ट्रेप' की लेखिका यूपन यूएन आंग का यह कथन एकदम सटीक है।

समृद्धि की कामना करनी होती है और उसका निर्माण करना होता है। यहां एक और बुनियादी प्रश्न उत्पन्न होता है? इसे कौन करेगा, और क्यों? दिलचस्प बात यह है कि विकास अर्थशास्त्र ने कभी भी समृद्धि की व्याख्या के केंद्र में नेतृत्व को नहीं रखा जबकि नेतृत्व यह तय कर सकता है कि कोई देश

सही समय पर सही आर्थिक और सामाजिक निर्णय लेता है या नहीं। विचारकों ने लंबे समय से यह समझाने की कोशिश की है कि कुछ राष्ट्र अमीर क्यों बनते हैं जबकि अन्य गरीब ही रहते हैं। डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डों ने आर्थिक वृद्धि को राजनीतिक अर्थशास्त्र का केंद्र माना लेकिन आधुनिक-वृद्धि सिद्धांत केवल 1940 के दशक में हैरोड-डोरम मॉडल और बाद में सोलो-स्वान ढांचे के साथ उभरा। सोलो ने स्थापित किया कि दीर्घकालिक वृद्धि पूंजी संचय, श्रम और तकनीकी प्रगति पर निर्भर करती है। 1980 के दशक से पॉल रोमर और रॉबर्ट लुकास ने मॉडल में तकनीक और ज्ञान सृजन को शामिल किया और नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, मानव पूंजी और 'सीखते हुए करने' को सतत वृद्धि के स्रोत के रूप में महत्व दिया।

संस्थागत अर्थशास्त्रियों जैसे डगलस नॉर्थ



और बाद में डैन एसेमोगलू तथा जेम्स रॉबिन्सन ने ध्यान को वृद्धि के गहरे निर्धारकों की ओर मोड़ा यानी संपत्ति अधिकां, शासन, कानून का शासन और राजनीतिक संस्थाएं। इन सिद्धांतों के साथ-साथ संरचनावादी स्कूल भी चला, जो पॉल रोसेनस्टीन-रोडान से जुड़ा था। उन्होंने तर्क दिया कि केवल बाजार गरीब देशों में समन्वय विफलताओं, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और संरचनात्मक कठोरताओं को दूर नहीं कर सकते। उन्होंने औद्योगिक नीति और सार्वजनिक निवेश का उपयोग करने वाले सक्रिय विकासशील राज्य की क्वालत की। विकासशील दुनिया में राज्य के हस्तक्षेप

के निराशाजनक परिणाम, 1980 के दशक के त्रुष संकट और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के पतन ने बौद्धिक सहमति को एक बार फिर बाजारों की ओर मोड़ दिया। वॉशिंगटन सहमति ने इस अदृश्य हाथ पर विश्वास को मूर्त रूप दिया यानी उदारीकरण, निजीकरण, नियम-कानून कम करना और व्यापक आर्थिक अनुशासन बनाए रखना। लेकिन यह भी अधूरा साबित हुआ। ध्यान दीजिए कि इस बौद्धिक इतिहास से क्या पायाब है- नेतृत्व।

यह आश्चर्यजनक है क्योंकि गरीब देशों जो क्लेयोट्स्क्रेट्स (ऐसे शासक जो सत्ता में रहते हुए राज्य की संपत्ति और संसाधनों का दुरुपयोग करके उसे निजी लाभ के लिए लूटते हैं) और जड़ जमाए हुए अभिजात वर्ग को राज्य पर कब्जा करने की अनुमति देते हैं। आर्थिक सिद्धांत में कितना भी सुधार कर लिया जाए, उससे विकास नहीं हो सकता,

जब राजनीतिक नेता तंत्र का फायदा खुद उठाने पर ही आमादा हों। नेतृत्व लगभग हर संगठन (सामाजिक या कॉर्पोरेट) में निर्णायक कारक होता है। तो फिर किसी देश के लिए यह अलग क्यों होना चाहिए? क्या कोई स्रोत है कि जमरेशकी टाटा ने टाटा साम्राज्य बनाने में केंद्रीय भूमिका नहीं निभाई या कि टेस्ला और स्पेसएक्स उतना ही अच्छा करते यदि इलॉन मस्क के अलावा कोई और उनका नेतृत्व करता? क्या इसे आंकड़ों से तय किया जा सकता है? अर्थशास्त्रियों बेंजामिन जोन्स और बेंजामिन ओल्कसन ने पद पर रहते हुए राष्ट्रीय नेताओं की आकस्मिक, बाहरी उरका से होने वाली मौतों का विश्लेषण किया। किसी नेता की अप्रत्याशित मृत्यु से ठीक पहले और बाद में आर्थिक प्रदर्शन को मापकर उनके शोध ने पाया कि कार्यकारी नेतृत्व दराल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि सकल में भारी बदलाव लाता है।

जल संरक्षण से भविष्य की जल सुरक्षा
का मॉडल गढ़ता छत्तीसगढ़

जल संचय-जन भागीदारी

अक्षय जल, सुरक्षित कल

कभी वर्षा आधारित कृषि और सीमित जल संरचनाओं वाले राज्य के रूप में पहचाना जाने वाला छत्तीसगढ़ आज जल संरक्षण, भू-जल संवर्धन, सिंचाई दक्षता और जनभागीदारी, आधारित जल प्रबंधन का राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभरा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जल संरक्षण को केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जनआंदोलन का स्वरूप दिया गया है। परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ आज 'जल सुरक्षा' की दिशा में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और केंद्र सरकार भी राज्य के नवाचारों को अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रही है। 'जल संचय-जन भागीदारी', 'एम-सीएडी मॉडल', 'जल जगार अभियान', 'डबरी निर्माण', 'भू-जल पुनर्भरण', 'वॉटर बजटिंग' और 'जल मित्र' जैसी पहलें विकसित छत्तीसगढ़ के जल प्रबंधन विजन को नई पहचान दे रही हैं। जल संरक्षण और जनसहभागिता के इस व्यापक अभियान ने राज्य में जल सुरक्षा की ऐसी मजबूत नींव रखी है, जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सुरक्षित बना रही है।



राष्ट्रीय पहचान बना छत्तीसगढ़ का जल संरक्षण मॉडल

केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य के कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन आधुनिकीकरण (M-CAD) मॉडल की सराहना करते हुए अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसे अपनाने की सलाह दी है। यह मॉडल सिंचाई दक्षता बढ़ाने, उपलब्ध जल संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक बूंद पानी का अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंचाने की दिशा में प्रभावी साबित हुआ है।



'जल संचय - जन भागीदारी' जनआंदोलन बना जल संरक्षण

अभियान के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। राज्य में बड़े पैमाने पर बोरवेल रिचार्ज, रूफटॉप रेन वाटर हास्टिंग, रिचार्ज शाफ्ट, सोक पिट और ओपन वेल रिचार्ज जैसी संरचनाओं का निर्माण किया गया। अब दूसरे चरण 'जल संचय जन भागीदारी 2.0%' के अंतर्गत राज्य ने 10 लाख जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।



भू-जल संवर्धन में दिखाई देने लगे सकारात्मक परिणाम

छत्तीसगढ़ में 4 लाख से अधिक जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है, जिसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में भू-जल स्तर में सुधार दर्ज किया गया है। विशेष रूप से क्रिटिकल एवं सेमी-क्रिटिकल ब्लॉकों पर फोकस करते हुए जल संरक्षण कार्यों का बड़ा हिस्सा उन्ही क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है।



चार लाख किसानों तक पहुंचेगी 'डबरी क्रांति'

रजत जयंती वर्ष के अवसर पर 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले 4 लाख से अधिक किसानों को खेतों में डबरी निर्माण के लिए प्रोत्साहित। डबरियां वर्षा जल संचयन का प्रभावी माध्यम बन रही है।



जल जगार : जल संरक्षण को मिला जनोत्सव का स्वरूप

धमतरी जिले के गंगरेल बांध में आयोजित 'जल जागर महोत्सव' ने जल संरक्षण को जनजागरूकता और सामाजिक भागीदारी के नए आयाम दिए हैं।



कोरिया का '5 प्रतिशत मॉडल' और रायपुर का रिचार्ज नवाचार

कोरिया जिले का प्रसिद्ध '5 प्रतिशत मॉडल', जिसमें किसान अपनी भूमि का 5 प्रतिशत हिस्सा जल पुनर्भरण के लिए समर्पित करते हैं, देशभर में सराहा गया है। रायपुर जिले का कम लागत वाला भू-जल रिचार्ज मॉडल भी जल संरक्षण के क्षेत्र में प्रभावी और व्यवहारिक समाधान के रूप में सामने आया है। ये पहलें सिद्ध करती हैं कि स्थानीय स्तर के नवाचार भी राष्ट्रीय परिवर्तन का आधार बन सकते हैं।



जशपुर बना प्राकृतिक जल संरक्षण का मॉडल जिला

घरों, विद्यालयों, शासकीय संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर बड़ी संख्या में सोक पिट बनाए जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कंटूर ट्रेच और वॉटर एब्जॉर्प्शन ट्रेच के माध्यम से वर्षा जल को संरक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही जिले में सैकड़ों आजीविका डबरियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे जल संरक्षण के साथ ग्रामीण आजीविका को भी मजबूती मिल रही है।



राष्ट्रीय जल पुरस्कारों से बढ़ा प्रदेश का गौरव

जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजनांदगांव, महासमुंद, बिलासपुर, बलौदाबाजार सहित प्रदेश के अनेक जिलों को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इन उपलब्धियों ने राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाई है।



सिंचाई दक्षता से कृषि समृद्धि की नई राह

सिंचाई क्षमता विस्तार, जल उपयोग दक्षता और आधुनिक जल प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से किसानों को वर्षभर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। जल संसाधनों के बेहतर उपयोग से बहुफसली खेती, बागवानी, सब्जी उत्पादन और कृषि आधारित रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है और किसानों की आय में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की जा रही है।

“

जल संरक्षण केवल पर्यावरण संरक्षण का विषय नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का संकल्प है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ ने जल संरक्षण को जनभागीदारी का अभियान बनाया है। जल संचय-जन भागीदारी, डबरी निर्माण, भू-जल पुनर्भरण, जल जगार और एम-सीएडी जैसे नवाचारों के माध्यम से हम जल सुरक्षा की मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य केवल जल संरचनाओं का निर्माण नहीं, बल्कि जल संरक्षण को जनसंस्कृति बनाना है। प्रत्येक गांव, प्रत्येक किसान और प्रत्येक नागरिक इस अभियान का सहभागी बने, यही हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में जल सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है।

— श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

विकसित छत्तीसगढ़ का जल संकल्प

“हर बूंद का संरक्षण — हर भविष्य की सुरक्षा”

जल संचय, जनभागीदारी, वैज्ञानिक जल प्रबंधन और तकनीकी नवाचारों के समन्वय से छत्तीसगढ़ आज देश को जल सुरक्षा का नया मार्ग दिखा रहा है। जल संरक्षण के क्षेत्र में राज्य द्वारा स्थापित यह मॉडल केवल वर्तमान की उपलब्धि नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत आधारशिला है।

संवाद-48628/1



जनभागीदारी से जल संरक्षण, जल संरक्षण से समृद्ध छत्तीसगढ़

